



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 10, 1976/चैत्र 21, 1898

No. 15]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 10, 1976/CHAITRA 21, 1898

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

**Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)**

निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1976

का० आ० 1265.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 260-दुधौ (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम प्रसाद, ग्राम घ पो० आ० बघारू, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्घीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्बन्ध सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम प्रसाद को संघ के किसी भी सदन के

या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/260/74(532)]

ELECTION COMMISSION

ORDER

New Delhi, the 24th January, 1976

S.O. 1265.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Prasad, Village and P. O. Bagharu, Distt. Mirzapur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 260-Dudhi (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Prasad to be disqualified for being chosen as and for

being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/260/74(532)]

आदेश

का० प्रा० 1266.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 260-दुधही (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जिनंद लाल, ग्राम सुपाचुआ, पो० आगिस आगपानी, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री जिनंद लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/260/74(533)]

ORDER

S.O. 1266.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jind Lal, Village Supachua, P. O. Agpani, District Mirzapur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 260-Dudhi (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jind Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/260/74(533)]

आदेश

का० प्रा० 1267.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 260-दुधही (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम मोहड़ा, पो० आ० नाधरा, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं

दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/260/74(534)]

ORDER

S.O. 1267.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rajendra Prasad Singh, Village Gohunda, P. O. Nadhira, Distt. Mirzapur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 260-Dudhi (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rajendra Prasad Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/260/74(534)]

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1976

का० प्रा० 1268.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 235-सादात निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिवमूरत सिंह, पो० कपूरपुर, शहर गाजीपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री शिवमूरत सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/235/74(535)]

ORDER

New Delhi, the 31st January, 1976

S.O. 1268.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shiv Murat Singh, Mohalla Kapur-pur, Ghazipur City, Distt. Ghazipur, Uttar Pradesh, a contesting candidate

for election to the U. P. Legislative Assembly from 235-Sadat assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shiv Murat Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/235/74(535)]

प्रादेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1976

का० प्रा० 1289 —यत् निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 263-चुनार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरि वंश, ग्राम ब पो० कोलना, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हरि वंश को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/263/74(536)]

ORDER

New Delhi, the 3rd February, 1976

S.O. 1269.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Haribansh, Village and P. O. Kolna, Distt. Mirzapur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 263-Chunar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Haribansh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/263/74(536)]

प्रादेश

का० प्रा० 1270 —यत् निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 266-छानवे (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मानिक चन्द, ग्राम ब पो० ब्राकम बरोधा, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मानिक चन्द को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/266/74(537)]

ORDER

S.O. 1270.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Manik Chand, Village and P.O. Baraundha, Distt. Mirzapur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 266-Chhanvey (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Manik Chand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/266/74(537)]

प्रादेश

का० प्रा० 1271 —यत् निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 281-खारा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एस० एम० हक, द्वारा श्री बजरज सिंह, गौतम नगर, फतेहपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एस० एम० हक को संसद् के किसी भी सदन

के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि०-सं०/281/74 (538)]

ORDER

S.O. 1271.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri S. M. Haq, C/o Shri Brajraj Singh, Gautam Nagar, Fatehpur, Distt. Fatehpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 281-Khaga assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri S. M. Haq to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/281/74(538)]

आदेश

का० आ० 1272.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 281-खागा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोह० मोबिन सिद्दीकी, मुहल्ला खेलदार, फतेहपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मोह० मोबिन सिद्दीकी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि०-सं०/281/74(539)]

ORDER

S.O. 1272.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohd. Mobin Siddiqui, Mohalla Kheldar, Fatehpur, Distt. Fatehpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 281-Khaga assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri

Mohd. Mobin Siddiqui to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/281/74 (539)]

आदेश

का० आ० 1273.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 281-खागा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामचन्द्र, ग्राम व पो० कटोघन, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री रामचन्द्र को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि०-सं०/281/74(540)]

ORDER

S.O. 1273.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Chandra, Village and P.O. Kotaghan, District Fatehpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 281-Khaga assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Chandra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/281/74(540)]

आदेश

का० आ० 1274.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 281-खागा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुन्दर लाल, ग्राम व पो० बैगाँव, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण

नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री सुन्दर लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/281/74(541)]

ORDER

S.O. 1274.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sundar Lal, Village and P. O. Baigaon, District Fatehpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 281, Khaga assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sundar Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/281/74 (541)]

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1976

आदेश

का० प्रा० 1275.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 232-जमानिया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरिहर सिंह, मु० सिकन्दरपुर, गाजीपुर शहर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री हरिहर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/232/74(542)]

ORDER

New Delhi, the 10th February, 1976

S.O. 1275.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Harihar Singh, Mohalla Sikandarpur, Ghazipur City Distt. Ghazipur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for

election to the U.P. Legislative Assembly from 232-Jamania assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Harihar Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/232/74 (542)]

आदेश

का० प्रा० 1276.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 258-गडवारा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री त्रिवेनी, ग्राम बरौली, पो० प्रा० बदनापुर, जिला जोनपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री त्रिवेनी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/258/74(543)]

ORDER

S.O. 1276.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tribeni, Village Barauli, P. O. Badlapur, Distt. Jaunpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 258-Garwara assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tribeni to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/258/74 (543)]

आदेश

नई दिल्ली 13 फरवरी, 1976

का० प्रा० 1277.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचन के लिए 238-चन्दौली सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दुर्गा प्रसाद, पुत्र श्री सीताराम ग्राम व पो० आफिस बबुरी, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत्, श्रीदुर्गा प्रसाद को जारी की गई सूचना अपरिचित वापस प्राप्त हो गई है क्योंकि अभ्यर्थी का ठीक ठिकाना विदित नहीं है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री दुर्गा प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[स० उ०प्र०-वि० स०/238/74(544)]

ORDER

New Delhi, the 13th February, 1976

S.O. 1277.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Durga Prasad, son of Shri Sita Ram, Village and P.O. Baburi, District Varanasi, U.P., a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 238-Chandauli Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the notice issued to Shri Durga Prasad has been received back undelivered as the whereabouts of the candidate are not known, and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure,

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Durga Prasad to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/238/74(544)]

आदेश

का० प्रा० 1278.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 265-मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हिरदय नारायण, मुहल्ला भटवा की पोखरी शहर मिर्जापुर, जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री हिरदय नारायण को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[स० उ०प्र०-वि० स०/265/74(545)]

ORDER

S.O. 1278.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hirdaya Narain, Mohalla Bhatwa Ki Pokhari, Mirzapur City Distt. Mirzapur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 265-Mirzapur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made there under ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hirdaya Narain to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/265/74(545)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1976

का० प्रा० 1279.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 308-कन्नौज (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कालीचरण, बाल्मीकि, ग्राम मलिकपुर, पो० प्रा० समाधान जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री कालीचरण बाल्मीकि को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[स० उ० प्र०-वि० स०/308/74(546)]

ORDER

New Delhi, the 21st February, 1976

S.O. 1279.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kahi Charan Balmiki, Village Malikpur, P. O. Samdhan, Distt. Farrukhabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 308-Kannauj (SC) assembly constituency, has failed to lodge

an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kali Charan Balmiki to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/308/74(546)]

आदेश

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1976

का० प्रा० 1280.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 389-मुरादनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सत्यपाल, ग्राम याकूतपुर मबी, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचनों व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री सत्य पाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/389/74(547)]

ORDER

New Delhi, the 26th February, 1976

S.O. 1280.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Satya Pal, Village Yakutpur Mawi, District Meerut, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 389-Muradnagar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Satya Pal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/389/74(547)]

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1976

का० प्रा० 1281 —यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 92 मरवाही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती कौशल्या देवी, ग्राम सुफरी, पो० रोरमी, जिला बिलासपुर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्रीमती कौशल्या देवी को समद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० म० प्र०-वि०स०/92/72(112)]

ORDER

New Delhi, the 4th March, 1976

S.O. 1281.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Kaushilya Debi, Village Sufri, P.O. Rormi, District Bilaspur who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 92-Marwahi constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declare the said Shrimati Kaushilya Debi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/92/72(112)]

आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1976

का० प्रा० 1282.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1974 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 16 पफुटसेली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रजौवीयी केजो, ग्राम किकलूम, पो० प्रा० पफुटसेली, जिला फेक (नागालैण्ड) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया

है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री रजौवोयो केजो को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० नागालैण्ड-वि०सं०/16/74]

ORDER

New Delhi, the 10th March, 1976

S.O. 1282.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Razouvoyo Kezo, Village Kikuma, P.O. Pfu-tero, District Phek (Nagaland) a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in February, 1974 from 16-Pfutsero constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Razouvoyo Kezo to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. NL-LA/16/74]

आदेश

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1976

क्र० आ० 1283.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 29-भानवाड निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्रतापनाराय सुखलाल घेलानी, जवाहर रोड, भानवाड, जिला जामनगर (गुजरात) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री प्रतापराय सुखलाल घेलानी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० गुज०-वि०सं०/29/75(34)]

ORDER

New Delhi, the 23rd March, 1976

S.O. 1283.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Prataprai Sukhlal Ghelani, Jawahar Road, Bhanvad, District Jamnagar (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 29 Bhanvad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Prataprai Sukhlal Ghelani to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/29/75(34)]

आदेश

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1976

क्र० आ० 1284.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 30-खम्भालिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कांजी वसाराम कन्जारिया, सततवारा चोरा के पास, खम्भालिया, जिला जामनगर (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री कांजी वसाराम कन्जारिया को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान-परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० गुज०-वि०सं०/30/75(35)]

ORDER

New Delhi, the 24th March, 1976

S.O. 1284.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kanji Vasaram Kanzariya, Near Satvara Chora, Khambhalia, District Jamnagar (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 30-Khambhalia constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kanji Vasaram Kanzariya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/30/75(35)]

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1976

कां०प्रा० 1285—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग तमिलनाडु सरकार के परामर्श से, श्री एच०के० गाजी के स्थान पर श्री एस०पी० श्रीनिवासन, पदेन विशेष अपर सचिव लोक (निर्वाचन) विभाग, तमिलनाडु सरकार, को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेशों तक तमिलनाडु राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में नाम निर्देशित करता है।

[सं० 154/तमिलनाडु/76]

ए० एन० सैन, सचिव

New Delhi, the 25th March, 1976

S.O. 1285.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with Government of Tamil Nadu, hereby nominates Shri S. P. Srinivasan, ex-officio Special Additional Secretary to Government, Public (Elections) Department as Chief Electoral Officer for the State of Tamil Nadu, with effect from the date he take charge of the office and until further orders vice Shri H. K. Ghazi.

[No. 154/TN/76]

A. N. SEN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1976

कां०प्रा० 1286.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन, के लिए 71-कालूपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री खासिम अली गुलाम अली मोमिन कालूपुर, पंचपट्टी, दह्यानी पोल् अहमदाबाद-1 (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री खासिम अली गुलाम अली मोमिन को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० गुज०वि०सं०/71/75(26)]

ORDER

New Delhi, the 11th March, 1976

S.O. 1286.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Khadimali Gulamali Momin, Kalupur, Panchpatti, Dahyani Pole Ahmedabad-1 (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 71-Kalupur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Khadimali Gulamali Momin to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/71/75(26)]

आदेश

कां०प्रा० 1287.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 72-असारवा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अनिल कुमार चीन्भार्ई पटेल, नावा अषारवा, अहमदाबाद-16 (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अनिल कुमार चीन्भार्ई पटेल को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० गुज०वि०सं०/72/75(27)]

ORDER

S.O. 1287.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Anilkumar Chinubhai Patel, Nawa Asarwa, Ahmodabad-16 (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 72-Asarwa constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure,

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Anilkumar Chinubhai Patel to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/72/75(27)]

आदेश

का० आ० 1288.—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 72-असारवा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री माथुरभाई अमथाभाई पटेल, 10, नावा प्रभुनगर सोमायटी, असारवा, अहमदाबाद (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है ; और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायी-चित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री माथुरभाई अमथाभाई पटेल को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० गुज०-वि०म०/72/75(28)]

ORDER

S.O. 1288.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mathurbhai Amthabhai Patel, 10, Nawa Prabhu-nagar Society, Asarwa, Ahmedabad (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 72-Asarwa constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mathurbhai Amthabhai Patel to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/72/75(28)]

आदेश

का० आ० 1289—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 76-जमालपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गुलाम मुस्तफा इस्माइल, 1393/2, कछिया पोल, कंचनी मसजिद, जमालपुर, अहमदाबाद (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायी-चित्य नहीं है ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री गुलाम मुस्तफा इस्माइल को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ;

[सं० गुज०-वि०म०/76/75(29)]

ORDER

S.O. 1289.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gulam Mustufa Ismail, 1393/2, Kachhia Pole, Kanchni Masjid, Jamalpur, Ahmedabad (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 76-Jamalpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gulam Mustufa Ismail to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/76/75(29)]

आदेश

का० आ० 1290—यत्, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 76-जमालपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मूसजी इसाकजी छिप्पा, 786, जमालपुर, पंच पिपली, खाराबला डेरा के निकट, लुहारवाडी के पीछे, अहमदाबाद (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत्, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायी-चित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मूसजी इसाकजी छिप्पा को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० गुज०-वि०म०/76/75(30)]

ORDER

S.O. 1290.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Musaji Isakji Chhipa, 786, Jamalpur, Panch Pipli, Near Kharwala Dera, Behind Luharwadi, Ahmedabad (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 76-Jamalpur constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Musaji Isakji Chhipa to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/76/75(30)]

आदेश

क्र० आ० 1291—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 76-जमालपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जोहरभाई फिदाहुसैन रूपवाला, 3634/3, अस्तोदिया, काजीनु धाबू, मोती बोरवाड़, अहमदाबाद (गुजरात) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री जोहरभाई फिदाहुसैन रूपवाला को संसद के किसी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[स० गुज०-वि०स०/76/75(31)]

ORDER

S.O. 1291.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Joharbhai Fidahussain Roopawala, 3634/3, Astodia, Kajinu Dhabu, Moti vorwad, Ahmedabad (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 76-Jamalpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Joharbhai Fidahussain Roopawala to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/76/75(31)]

आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1976

क्र० आ० 1292—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के

लिए 73-रखिआल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरगोविन्दभाई भीखाभाई सोलंकी, 64, जमनानगर शास्त्री स्टेडियम के पीछे, अहमदाबाद-23 (गुजरात) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई कारण या न्यायोचित्य नहीं है

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री हरगोविन्दभाई भीखाभाई सोलंकी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[स० गुज०-वि०स०/73/75(32)]

ORDER

New Delhi, the 12th March, 1976

S.O. 1292.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hargovindbhai Bhikhabhai Solanki, 64, Jamnanagar, Behind Shastri Stadium, Ahmedabad-23, (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 73-Rakhial constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hargovindbhai Bhikhabhai Solanki to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/73/75(32)]

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1976

क्र० आ० 1293—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 109-बायद निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दशरथलाल नाथलाल रामी, मकान सं० 7/35, बेर्जीवाडा, साथम्बा, डाकखाना साथम्बा, साल्लुका बायद, जिला सबरकण्ठा (गुजरात), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री दशरथलाल नाथलाल रामी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० गुज०-वि०सं०/109/75(33)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th March, 1976

S.O. 1293.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dasharathlal Nathlal Rami, House No. 7/35, Darjiwada, Sathamba, Post Sathamba, Taluka Bayad, District Sabarkantha (Gujarat), a contesting candidate in the general election held in June, 1975 to the Gujarat Legislative Assembly from 109-Bayad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dasharathlal Nathlal Rami to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/109/75(33)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

बिधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1976

नोटिस

का० प्रा० 1294.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री मोहन लाल गुग्गोहेट एडवोकेट, बीकानेर (राजस्थान) ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, बीकानेर जिले में लेख्य प्रमाणक (नोटरी) का काम करने की नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र भेजा है।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियाँ हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्तर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें।

[संख्या 22/43/75-न्याय]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

New Delhi, the 9th March, 1976

Notice

S.O. 1294.—Notice is hereby given by the Company Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule

4 of the said Rules, by Shri Mohan Lal Purohit, Advocate, Bikaner for appointment as a Notary to practise in Bikaner Distt. at Bikaner (Rajasthan).

Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/43/75-Justice]

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1976

नोटिस

का० प्रा० 1295.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री इन्द्रजीत शाह एडवोकेट, 61/3, कबाडी बिल्डिंग, चौदेरवरी मंदिर मार्ग, बंगलूर-2 ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, बंगलूर में लेख्य प्रमाणक (नोटरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र भेजा है।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियाँ हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्तर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें।

[संख्या 22/19/76-न्याय]

प्रा० एल० परदीप, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 19th March, 1976

Notice

S.O. 1295.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Indrajeet Shah, Advocate 61/3, Kabadi Building Chowarwari Temple Street, Bangalore, for appointment as Notary to practise in Bangalore, (Karnataka).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/19/76-Jus]

R. L. PARDEEP, Dy. Secy.

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1976

का० प्रा० 1296.—एकधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सैसर्स चोगुले कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 320/70 दिनांक 26-10-1970) के निरस्तीकरण को अधिमूर्चित करती है।

[संख्या 2/19/73-एम०-2]

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 22nd March, 1976

S.O. 1296.—In pursuance of sub-section (3) of section 26

of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of registration of M/s. Chowgule Chemicals Private Limited under the said Act (certificate of registration No. 320/70 dated 26-10-1970).

[No. 2/19/73-M. II]

का० प्रा० 1297.—एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स कैमेरा वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 456/70 दिनांक 30-10-1970) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[संख्या 2/33/75-एम० 2]

S.O. 1297.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of registration of M/s. Camera Works Private Limited under the said Act (certificate of registration No. 456/70 dated 30-10-1970).

[No. 2/33/75-M. II]

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1976

का० प्रा० 1298.—एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स आटो लाइनर्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड, के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 44/70 दिनांक 19-10-1970) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[संख्या 2/50/75-एम० 2]

एम० सी० वर्मा, उप सचिव

New Delhi, the 24th March, 1976

S.O. 1298.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of registration of M/s. Auto Liners (Madras) Private Limited under the said Act (certificate of registration No. 44/70 dated 19-10-1970).

[No. 2/50/75-M. II]

M. C. VARMA, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1976

का० प्रा० 1299.—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, निदेश देते हैं कि सभी सच राज्यक्षेत्रों के प्रशासक (चाहे उन्हें उप राज्यपाल, मुख्य आयुक्त या प्रशासक कहा जाता हो), राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक, बंधकाधीन श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19) की धारा 10, धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन, अपने-अपने संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर, राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन भी करेंगे ।

[सं० यू०-11030/5/75-यू टी० एल०]

हरीश चन्द्र बखशी, अधवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 26th March, 1976

S.O. 1299.—In pursuance of clause (1) article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators of all Union territories (whether known as Lieutenant Governors, Chief Commissioners or Administrators) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under section 10, sub-section (1), and clause (d) of sub-section (2), of section 13 and sub-section (1) of section 21 of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (19 of 1976), within their respective Union territories.

[No. U-11030/5/75-UTL]

H. C. BAKSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1976

का० प्रा० 1300.—केन्द्रीय सरकार ने, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1937 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 अगस्त, 1975 को मिजो राष्ट्रीय मोर्चा और उसके द्वारा गठित अन्य निकायों को, जिसमें तथाकथित मिजो राष्ट्रीय सेना भी है, विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 29 अगस्त, 1975 को, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण गठित किया है जिसके पीठासीन अधिकारी गोंगाटो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री डी० एम० सेन हैं ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना को 2 सितम्बर, 1975 को उक्त अधिकरण को यह न्यायनिर्णय करने के प्रयोजन से निविष्ट किया था कि क्या उक्त संगठनों को विधि विरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 जनवरी, 1976 को एक आदेश किया ;

इसलिये, अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त अधिकरण के उक्त आदेश को प्रकाशित करती है, अर्थात् —

आदेश

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के समक्ष (अंग्रेजी में प्रकाशित अधिसूचना देखिये) ।

[सं० 111-14014/40/75-एन ई-1]

New Delhi, the 31st March, 1976

S.O. 1300.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), declared on the 5th August, 1975, the Mizo National Front and the other bodies set up by it, including the so-called Mizo National Army, to be unlawful associations;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the said Act, constituted on the 29th August, 1975, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, consisting of Mr. Justice D. M. Sen, Judge of Gauhati High Court.

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, referred the said notification to the said Tribunal on the 2nd September, 1975, for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the said associations unlawful;

And whereas the said Tribunal, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, made an order on the 29th January, 1976;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (4) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby publishes the said Order of the said Tribunal, namely:—

BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

Reference made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (Act 37 of 1967).

In Re: Mizo National Front and other allied bodies including the so-called Mizo National Army.

PRESENT:

The Hon'ble Mr. Justice D. M. Sen.

APPEARANCE:

For the Mizo National Front and : None appears.
other allied bodies including the
so-called Mizo National Army.

For the Union of India : Mr. A.R. Barthakur,
Sr. Advocate
Mr. H. K. Sema,
Advocate.

Venue of the sitting : No. 1 Maulana Azad
Road, New Delhi.

Dates of hearing : 17th, 19th and 23rd of
Jan. 1976.

Date of Order : 29th Jan, 1976.

ORDER

Sen, J.—This Tribunal was constituted on 29th August, 1975 by the Central Government in exercise of its powers under Section 5(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967. The Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 419(E) published in the Gazette of India Extra-ordinary dated the 5th August, 1975, declaring the "Mizo National Front" and the other bodies set up by it, including the so-called "Mizo National Army" to be unlawful Associations has been referred to this Tribunal, as required under Section 4 of the aforesaid Act.

On receipt of the Reference under Section 4(1) of the Act, the so-called 'Mizo National Army' and other bodies set this Tribunal had called upon the "Mizo National Front" up by the Front to show cause as to why these Associations, should not be declared unlawful. Notices were duly served as required under the Act and rules made thereunder, but none of these Associations have made appearance. The Central Government, however, made appearance before this Tribunal on several dates. It also examined two witnesses, namely, Mr. P. P. Shrivastav, Director, N. E. Ministry of Home Affairs, New Delhi and Shri F.L.R. Siamia, Assistant Inspector General of Police, Mizoram. The Central Government also filed an affidavit in support of the notification issued on August 5, 1975 and produced through its witnesses several documents in support of the declaration in the above Notification.

I have framed the following issues in order to determine whether the aforesaid Notification may be confirmed or not. The issues framed by me are stated below:

- (1) Whether the Mizo National Front hereinafter referred to as "the Front" has openly declared as its objective the formation of an independent

Mizoram comprising the Union Territory of Mizoram and the adjacent Mizo and Kuki inhabited areas of Manipur and Tripura.

- (2) Whether the Front has been continuing its activities and policy to achieve the said objective and bring about cessation of the said areas from the Union of India.
- (3) Whether the Front has set up an Organisation and other bodies including an armed force, the so-called Mizo National Army to achieve its objectives specified in Issue No. 1 and 2 above.
- (4) Whether the Front has, in furtherance of its objectives, been employing the said armed force referred to in Issue No. 2 above, in attacking the Security Forces, the Civil Government and the citizens in the Union Territory of Mizoram, Cachar, district of Assam, Manipur and Tripura and indulging in acts of arson, looting, intimidation against the civilian population and recruitment of persons and collection of funds for its organisation.
- (5) Whether the Front has, to achieve its objective mentioned in Issue No. 1 above, maintained contacts with foreign countries through its organisation and armed force with a view to securing finance and armed assistance and training for the so-called Mizo National Army and has secured such assistance.
- (6) Whether the Central Government is justified in issuing Notification No. S.O. 419(E) dated New Delhi the 5th August, 1975 published in the Gazette of India.

in its issue No. 295 dated New Delhi August 5, 1975, declaring the Mizo National Front and the other bodies set up by it including the so-called Mizo National Army to be unlawful associations and the said notification may be confirmed or is liable to be cancelled.

I shall first examine the evidence relating to Issue No. 1, that is to say, whether the Mizo National Front had as one of its objectives the formation of an independent Mizoram, comprising the Union Territory of Mizoram and the adjacent Mizo and Kuki inhabited areas of Manipur and Tripura. In this connection, I may refer to the evidence of Mr. P. P. Shrivastav, Director, N. E. Ministry of Home Affairs, who has been dealing with, in the Central Government, the affairs of Mizoram. He has stated in his evidence: "the M.N.F. and M.N.A. are trying for the secession of Mizoram and its adjacent territories inhabited by Mizos, Kukis and allied tribes from the Indian Union. The M.N.F. was formed in September, 1960. It had made a demand for Independence in 1961 and had started armed insurrection in 1966." I have also seen the evidence of P.W. 2, Mr. F.L.R. Siamia, A.I.G.P. Mizoram, who produced before me certain documents seized by the Security Forces from the Mizo National Front in course of operations against them. I find that Ext. 4 contains the Constitution of the Mizo National Front and also the declaration of Independence. A reference to the so-called Constitution of Mizoram (Ext. 4) makes it quite clear that one of the aims of the Mizo National Front is to set up an independent Government over the people of Mizoram as if Mizoram were not an integral part of India. The territory which the Mizo National Front claims to be a sovereign Republic is clearly demarcated in a map prepared under the authority M.N.F. (Ext. 14). I find from Ext. 14 that this territory comprises not only the Union Territory of Mizoram, but also certain adjoining territories of Manipur, Cachar, Burma and Bangladesh, stated to be inhabited by Mizo tribes. I am thus left with no doubt whatsoever that the M.N.F. had, as one of its primary objects, the formation of an independent State of Mizoram, comprising the Union Territory of Mizoram and the adjacent Mizo and Kuki inhabited areas of Manipur and Tripura.

Issue No. 2 relates to the activities and policy of the Mizo National Front, calculated to achieve its object of attaining the independence of Mizoram. There is the clear evidence of Mr. P. P. Shrivastav and of Mr. F.L.R. Siamia showing that the M.N.F./M.N.A. have been carrying on operations involving violence, in order to achieve the above objective. For example, Ext. 6 contains the instructions issued to M.N.F. Intelligence, Ext. 8 is the Work Policy issued by

the M.N.F., Ext. 10 is the exhortation by Laldenga to march towards freedom, Ext. 11 is a duty report by M.N.F. functionary address to the Chairman, M.N.F. Committee, Ext. 12 is a document relating to distribution of ration money issued by the Chief of the Army Staff of the Mizo National Army and Ext. 13 is an operation order issued by the Chief of the Army Staff of the M.N.F. All these would indicate that the M.N.F. and M.N.A. had been continuously striving towards the attainment of its objective and that it was not merely an abstract visionary idea on their part. These associations have been indulging in every sort of over act, involving violence, in order to achieve the aforesaid objective.

Issue No. 3 relates to the setting up of an Armed Force, known as Mizo National Army by the M.N.F. The documents, which I have referred to above, clearly indicate that the M.N.A. had been set up by the M.N.F. in order to achieve its objective of secession from India and constitution of an independent Mizoram.

The fourth issue relates to the several activities of the M.N.F. viz. attacking the Security Forces, the Civil Government and intimidating the citizens of Union Territory of Mizoram, Cachar, Manipur and Tripura and indulging in acts of arson, looting and intimidation. The evidence of P.W. 1 and P.W. 2 fully supports the allegations, which are covered by this issue. I have also seen the interrogation report of Colonel Haleluia, from which it is quite clear that the M.N.A. had been collecting arms from the erstwhile East Pakistan, been establishing armed camps at several places both inside and outside Mizoram. I have also seen the operation order Ext. 13 which clearly proves that the M.N.F. and the M.N.A. wanted to infiltrate into Mizoram for operational purposes. I have also seen Ext. 8(1) which is the work policy of the M.N.F. and the M.N.A. This Work Policy requires that all Mizoram freedom fighters must get money, goods and other things from the enemy, by which term they mean the people of India. They also declared in this Work Policy that compulsory taxes were to be levied and collected in accordance with the schedule stated therein and that anyone who refused to pay taxes would have to bear the consequences. The allegations covered by this issue are fully borne out by the evidence on record.

The fifth issue relates to the maintenance of contact with foreign countries in order to achieve the objective of the M.N.F. The evidence, which I have discussed above amply bears out that the M.N.A. has been maintaining contact and liaison with foreign countries in order to achieve its objective of setting up a sovereign independent State of Mizoram.

I have carefully examined all the evidence that has been produced before me, both oral and documentary. In doing so, I have taken all caution that is normally necessary where the matter is being heard *ex parte*. Bearing all these considerations in mind, I have no doubt if any nature whatsoever that the M.N.F. and M.N.A. and other bodies set up by it had been committing acts, intended to bring about secession of the Union Territory of Mizoram from India and disclaiming the sovereignty and disrupting the territorial integrity of India. The Mizo National Front, the so-called Mizo National Army and other bodies set up by the Front, are clearly unlawful associations as defined in Section 2(g) of the Unlawful Activities (Prevention) Act and the Central Government was fully justified in declaring the above Associations to be unlawful, in exercise of its powers under Section 3(1) of the Act. The grounds stated in the Notification No. S.O. 419(F) dated the 5th August, 1975 and other particulars as contained in that Notification are fully borne out by the evidence on record, and the declaration cannot, in any way, be challenged as being without a valid basis. In point of fact, as I see it, the Central Government would have failed in its statutory duty, if it had not declared these associations to be unlawful. All the issues are accordingly answered in the affirmative. I, therefore, confirm the declaration in the said Notification under Section 4(3) of the Act.

While confirming the declaration as above, I only hope that all right thinking Mizos will henceforth desist from any further participation in these unlawful associations and join the mainstream of Indian political life, so that they can contribute to the development and welfare of Mizoram, as an integral part of the Union of India. The Constitution of India provides for and guaranteed Liberty, Equality and Justice to every Indian citizen, irrespective of caste, creed, race or community. Any citizen of India, who has been misled by the

evil and false propaganda, external or internal, should realise this and contribute his mite to build up a prosperous and powerful Indian Nation.

D. M. SEN, Member, Tribunal

[No. III-14014/40/75-NE-I]

का० प्रा० 1301—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का प्रा० 419(प्र) तारीख 5 अगस्त, 1975 में अन्तर्विष्ट विषय पर व्यापक निर्णय करने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० 457-प्र तारीख 29 अगस्त, 1975 द्वारा गठित "विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" ने, जिसमें गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री डी० एम० सेन थे, अपना कार्य पूर्ण कर लिया है ;

श्रीर केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त अधिकरण का निरन्तर अस्तित्व में रहना अनावश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्सादित करती है ।

[सं०-III 14014/40/75-एन० ई०-II]

प्रमोद प्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक

S.O. 1301.—Whereas the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice D. M. Sen, Judge of the Gauhati High Court, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 457-E dated the 29th August, 1975, to adjudicate upon the matter contained in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 419(E) dated the 5th August, 1975 has completed its work;

And whereas the Central Government is of opinion that the continued existence of the said Tribunal is unnecessary ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities, (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby abolishes the said Tribunal with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. III-14014/40/75-NE-II]

P. P. SHRIVASTAV, Director

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1976

(आय-कर)

का० प्रा० 1302—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री कलाहम्प्यीम्बरन स्वामी विरुकोइल, डिण्डीमुल को, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र, विख्यात लोकपूजा का म्यान अधिसूचित करती है ।

[सं० 1228/का० सं० 176/5/76-आई० टी० ए० आई०]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Banking)

New Delhi, the 12th February, 1976

INCOME-TAX

S.O. 1302.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies Sri Kalahastheeswaran Swami Thirukoli, Dindigul to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said section.

[No. 1228/F. No. 176/5/76-IT. AI]

M. SHASTRI, Under Secy.

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1976

सीमा-शुल्क

क्रा० प्रा० 1303.—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क कलक्टर, मद्रास, उप सीमाशुल्क कलक्टर, विशाखापत्तनम और सहायक सीमाशुल्क कलक्टर, विशाखापत्तनम को आन्ध्र प्रदेश राज्य में विशाखापत्तनम जिले के नथ्ययापालेम ग्राम के लिए क्रमशः सीमाशुल्क कलक्टर, उप सीमाशुल्क कलक्टर और सहायक सीमाशुल्क कलक्टर, नियुक्त करती है।

[अधिसूचना सं० 65/फा० सं० 437/5/76-सीमा शुल्क IV]

एच० नारायण राव अवर सचिव

(Revenue Wing)

New Delhi, the 10th April, 1976

CUSTOMS

S.O. 1303.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints the Collector of Customs, Madras, the Deputy Collector of Customs, Vishakhapatnam and the Assistant Collector of Customs, Vishakhapatnam to be respectively the Collector of Customs, the Deputy Collector of Customs and the Assistant Collector of Customs for Nathayyapalem village in the district of Vishakhapatnam, State of Andhra Pradesh.

[Notification No. 65/F. No. 437/5/76-Cus. IV]

H. NARAYAN RAO, Under Secy.

(Department of Banking)

ERRATA

New Delhi, the 19th March, 1976

S.O. 1304.—In the notification of the Ministry of Finance (Department of Banking) No. S.O. 7 [No. F. 8/4/75-AC] dated the 18th December, 1975 published at page 6 of the Gazette of India—Part II, Section 3(ii), dated the 3rd January, 1976, the figures & words "31 October, 1974 to 20 February 1976" shall be read as "31 October, 1974 to 29 February 1976".

[No. F. 8/4/75-AC]

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1976

क्रा० प्रा० 1305—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश

पर, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के और बैंककारी विनियमन (सहकारी समिति) नियम, 1966 के नियम 10 के उपबन्ध 'अध्यापक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुथूपल्ली (केरल)' पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका सम्बन्ध 30 जून, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष की इसके तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाते तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन से है।

[संख्या एक० 8/7/76-ए० सी०]

हृषी केश गुहा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 1976

S.O. 1305.—In exercise of the powers conferred by section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 31 of the said Act and Rule 10 of the Banking Regulation (Co-operative Societies) Rules, 1966 shall not apply to the 'Adhyapaka Co-operative Bank Ltd., Puthuppally (Kerala), in so far as they relate to the publication of its balance sheet, profit and loss account for the year ended the 30th June, 1975 together with the auditor's report in a newspaper.

[No. F. 8/7/76-AC]

H. K. GUHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1976

क्रा० प्रा० 1306.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री शिव शर्मा को चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 21 मार्च, 1976 से आरम्भ होकर 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमें श्री शिव शर्मा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एक० 4-69/75-ए० सी० (IV)]

New Delhi, the 21st March, 1976

S.O. 1306.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government appoints Shri Shiv Sharma as the Chairman of the Champaran Kshetriya Gramin Bank and specifies the period commencing on the 21st March, 1976 and ending with the 30th September, 1976 as the period for which the said Shri Shiv Sharma shall hold office as such Chairman.

[No. F. 4-69/75-AC (IV)]

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1976

क्रा० प्रा० 1307—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री प्रार० सी० बुद्धिराजा को गुडगांव ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 28 मार्च, 1976 से आरम्भ होकर 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमें श्री प्रार० सी० बुद्धिराजा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एक० 4-85/75-ए० सी० (4)]

क० पी० ए० मेहन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 28th March, 1976

S.O. 1307.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government appoints Shri R. C. Budhiraja as the Chairman of the Gurgaon Gramin Bank and specifies the period commencing on the 28th March, 1976 and ending with 30th September, 1976 as the period for which the said Shri R. C. Budhiraja shall hold office as such Chairman.

[No. F. 4-85/75-AC (IV)]

K. P. A. MENON, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1976

क्रा० प्रा० 1308.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री कंवर वीरेन्द्र सिंह गुप्ता को बाराबंकी ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 27 मार्च, 1976 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि को उस

अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमें श्री कंवर वीरेन्द्र सिंह गुप्ता अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं० एक० 4-93/75-ए० सी० (4)]

क० भवानी, उप सचिव

New Delhi, the 27th March, 1976

S.O. 1308.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government appoints Shri Kanwar Virendra Singh Gupta as the Chairman of the Barabanki Gramin Bank and specifies the period commencing on the 27th March, 1976 and ending with the 30th September, 1976 as the period for which the said Shri Kanwar Virendra Singh Gupta shall hold office as such Chairman.

[No. F 4-93/75-AC (IV)]

K. BAVANI, Dy. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1976

क्रा० प्रा० 1309.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में मार्च 1976 के दिनांक 12 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

इस विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	24,29,46,000		सोने का सिक्का और बुलियन—		
संचालन में नोट	6650,08,42,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,51,000	
			(ख) भारत के बाहर		
जारी किये गये कुल नोट		6674,37,88,000	रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां	271,73,97,000	
			जोड़		454,26,48,000
			रुपये सिक्का		9,66,91,000
			भारत सरकार की रुपया		
			प्रतिभूतियां 1		6210,44,49,000
			देशी विनिमय बिल और		
			दूसरे वाणिज्य-पत्र		..
कुल देयताएं		6674,37,88,000	कुल आस्तियां		6674,37,88,000

दिनांक : 18 मार्च, 1976

क० प्रार० पुरी, गवर्नर

12 मार्च, 1976 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यालय का विवरण

देयताएं	रुपये	प्राप्तियां	रुपये
चुक्ता पूंजी	5,00,00,000	नोट	24,29,46,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,05,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	छोटा सिक्का	4,75,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	110,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	(क) देशी	174,78,47,000
		(ख) विदेशी	..
जमा राशियां :		(ग) सरकारी खाजाना बिल	346,12,44,000
(क) सरकारी :		विदेशों में रखा हुआ बकाया *	1129,54,45,000
		निवेश**	3552,03,52,000
		ऋण और अग्रिम —	
(i) केन्द्रीय सरकार	196,36,00,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	9,49,46,000	(ii) राज्य सरकारों को†	95,14,20,000
(ख) बैंक :		ऋण और अग्रिम —	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	540,26,43,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को‡	726,66,55,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	17,02,99,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को@@	373,69,50,000
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,90,68,000	(iii) दूसरों को	11,64,82,000
(iv) अन्य बैंक	52,66,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :	
		(क) ऋण और अग्रिम :	
		(i) राज्य सरकारों को	69,13,00,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	15,05,72,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को	85,30,00,000
(ग) अन्य	1557,01,05,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	
देय बिल	159,94,72,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	10,11,46,000
अन्य देयताएं	915,73,15,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	88,52,61,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	378,19,32,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडो/ डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य प्राप्तियां	533,93,82,000
रुपये	4417,27,14,000	रुपये	4417,27,14,000

*नकदी, आबधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट्स शामिल हैं।

‡भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 49,84,50,000 रुपये शामिल हैं।

@ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

के० आर० पुरी, गवर्नर

दिनांक : 18 मार्च, 1976

[फा० सं० 10(1)/76-बो० प्रो० I]

च० व० मीरजखानी, अवर सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 23rd March, 1976

S. O. 1309.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 12th day of March, 1976
ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	24,29,46,000		Gold Coin and Bullion:—		
Notes in circulation	6650,08,42,000		(a) Held in India	182,52,51,000	
Total notes issued		6674,37,88,000	(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	271,73,97,000	
			Total		454,26,48,000
			Rupee Coin		9,66,91,000
			Government of India Rupee Securities		6210,44,49,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		6674,37,88,000	Total Assets		6674,37,88,000

Dated the 18th day of March 1976

K. R. PURI, Governor.

Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 12th March 1976

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid up	5,00,00,000	Notes	24,29,46,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	3,05,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	Small Coin	4,75,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	14,00,00,000	Bills Purchased and Discounted:—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(a) Internal	174,78,47,000
Deposits:		(b) External	
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	346,12,44,000
(i) Central Government	196,36,00,000	Balances Held Abroad*	1129,54,45,000
(ii) State Governments	9,49,46,000	Investments**	355,03,52,000
(b) Banks:		Loans and Advances to:	
(i) Scheduled Commercial Banks	540,26,43,000	(i) Central Government	..
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	17,02,99,000	(ii) State Governments†	95,14,20,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,90,68,000	Loans and Advances to:	
(iv) Other Banks	52,66,000	(i) Scheduled Commercial Banks‡	726,66,55,000
(c) Others	1557,01,05,000	(ii) State Co-operative Banks@	373,69,50,000
Bills Payable	159,94,72,000	(iii) Others	11,64,82,000
Other liabilities	915,73,15,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loan and Advances to:	
		(i) State Governments	69,13,00,000
		(ii) State Co-operative Banks	15,05,72,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) Agricultural Refinance & Development Corporation	85,30,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage bank Debentures	10,11,46,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	88,52,61,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	378,19,32,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	533,93,82,000
	Rupees 4417,27,14,000		Rupees 4417,27,14,000

* Includes Cash, Fixed Deposits and Short term Securities.

** Excluding Investments, from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

† Excluding loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

‡ Includes Rs. 49,84,50,000 advanced to Scheduled Commercial Banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

K. R. PURI, Governor

[No. F. 10(1)/76-BOI]

Dated the 18th day of March 1976

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy

समाहर्ता सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय :

गुंटूर, 21 फरवरी, 1976

सीमाशुल्क

का० आ० 1310—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के खण्ड (ए) के अधीन अधिसूचना सं० 79 कस्टम्स/एफ० नं० 473/2/75 कस्टम्स VII दिनांक 18 जुलाई, 1975 के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्यायोजित और सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में जिला विशाखापट्टणम के विशाखापट्टणम तालुक के नातय्यपालेम गांव को भाण्डागारण आस्थान घोषित करता हूँ।

[अधिसूचना सं० 1/कस०/76—सी० नं० viii/40/1/76(कस० टी०)]

पी० आर० कृष्णन, समाहर्ता

Office of the Collector of Central Excise

Guntur, the 21st February, 1976

CUSTOMS

S.O. 1310.—In exercise of the powers conferred by Sec. 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), as delegated by the Ministry of Finance vide Notification No. 79—Customs/F. No. 473/2/75—Customs VII dated 18th July, 1975, under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), I hereby declare Nathayyapalem village of Visakhapatnam Taluk of Visakhapatnam District in the State of Andhra Pradesh, to be a warehousing Station.

[No. 1/Cus/76—C. No. VIII/40/1/76 (Cus. T)]

P. R. KRISHNAN, Collector

समाहर्ता कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

बंगलूर, 6 नवम्बर, 1975

शुद्धि-पत्र

का० आ० 1311.—इस समाहर्तालय की दिनांक 25 नवम्बर, 1968 की अधिसूचना सं० 4/68 में निम्नलिखित संशोधन करने का आदेश दिया जाता है।

इस कार्यालय की ऊपर बतायी गई अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी की क्रम सं० 2 तथा उसके सामने की गई प्रविष्टियाँ निकाल दी जाएगी।

[अधिसूचना सं० 7/75-डी/डी]

एस० वेण्कटरामन अइयर, समाहर्ता

Office of the Collector of Central Excise

Bangalore, the 6th November, 1975

CORRIGENDUM

S.O. 1311.—In following amendment to this Collectorate Notification No. 4/68 dated 25-11-1968 is ordered with immediate effect :—

Serial No. 2 and the entries made against it in the table appended to this office Notification cited above shall be deleted.

[Notification No. 7/75 D/D]

S. VENKATARAMAN, IYER, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1976

(समुद्री उत्पाद उद्योग विकास नियन्त्रण)

का० आ० 1312.—समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 5253 दिनांक 13 दिसम्बर, 1975 की अधिसूचना द्वारा गठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से 12 दिसम्बर, 1978 तक निम्नोक्त व्यक्ति को सदस्य के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है।

“30. श्री वयालार रवि, संसद सदस्य अधिनियम की धारा 4(3)(vi) के अन्तर्गत अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।”

[स० 5/14/75-ई० पी० एग्री० II]

वि० शेषन, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Export Production)

New Delhi, the 23rd March, 1976

(Marine Products Industry Development Control)

S.O. 1312.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972) read with the rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, the Central Government hereby appoints with immediate effect the following person to be a member of the Marine Products Export Development Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, S.O. No. 5253 dated the 13th December, 1975, upto 12th December, 1978 :—

“30. Shri Vyalar Ravi, M.P.
To represent other
interests under Section
4(3)(vi) of the Act.”

[No. 5/14/75-EP(Agri. II)]

V. SESHAN, Under Secy.

मध्य निर्यात, आयात-निर्यात का कार्यालय

प्रावेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1976

का० आ० 1313.—निदेशक बिड़ला इन्सीट्यूट आफ टेक्नालोजी, मेसरा पी० आर० रावी-835215, बिहार को 2,00,000 रुपए ओ कि बाद में 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपए मात्र) बढ़ा दिया गया था, के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या जी/ए/1366695/सी/एक्स-एक्स/55/एच/39-40/आई एल एस, दिनांक 11-4-75 प्रदान किया गया था उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनियम नियन्त्रण प्रयोजन प्रतियों की अनुसूचि प्रतियाँ जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनियम नियन्त्रण प्रयोजन प्रतियाँ जो गई/अस्था-

नस्थ हो गई हैं। आगे यह बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां भारत के किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं करवाई गई हैं तथा उनका बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया है। इसमें शेष उपलब्ध धन राशि 2,50,000 रुपये थी।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने कार्यपालक वंड अधिकारी, रांची से स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां खो गई हैं अतः समय-समय यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निदेशक, बिड़ला इन्स्टी-ट्यूट ऑफ टेक्नालोजी, मेसरा पी० आर० रांची, बिहार को जारी किए गए उक्त लाइसेंस संख्या जी/ए/1366695/सी/एक्स एक्स/55/एच/39-40/आई एल एस, दिनांक 11-4-1975 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

3. उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनामुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों की अनुलिपि प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं।

[संख्या बी-13/इन्स्ट/74-75/आई एल एस/1836]

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

ORDER

New Delhi, the 10th February, 1976

S.O. 1313—The Director, Birla Institute of Technology, Mesra P.O. Ranchi-835215, Bihar were granted an import licence No. G/A/1366695/C/xx/55/H/39-40/ILS dated 11-4-75 for Rs. 2,00,000 subsequently raised to Rs. 2,50,000. (Rupees 2,50,000 only). They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes/Exchange Control purposes copies of the said licence on the ground that the original customs Purposes/Exchange Control copy have been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes/Exchange Control copy have not been registered with any customs in India and have not utilised at all. The balance available on it was Rs. 2,50,000.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit on a stamped paper from Karya Palak Dand-Adehkari, Ranchi. I am accordingly satisfied that the original customs purpose/Exchange control purpose copy of the said licence have been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) order 1955 dated 7-12-55 as amended from time to time the said original customs purpose exchange control purposes copies of licence No. G/A/1366695/C/xx/55/H/39-40/ILS dt. 11-4-75 issued to the Director, Birla Institute of Technology Mesra P.O. Ranchi, Bihar, are hereby cancelled.

3. The duplicate customs purposes/Exchange Control Purposes copies of the said licence are being issued separately to the licensee.

[No. B-13/Instt/74-75/ILS./1836]

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च 1976

का० आ० 1314—सर्वश्री कुमार टैक्सी, पैलेस रोड, कोचीन अप्रैल-मार्च 75 की रेडबुक (वा०-1) परिशिष्ट 26 सूची नं० 2 (भाग क तथा ख) के अन्तर्गत आने वाले भ्रमणकारी टैक्सियों के फालतू पुर्जों के आयात के लिए 2000 रुपये का एक आयात लाइसेंस संख्या पी/ए/1400386, दिनांक 15-6-74 प्रदान किया गया था। पार्टी ने लाइसेंस की दोनों प्रतियां बिना किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए थे उनका बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो दी हैं। अब पार्टी ने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति तथा मुद्रा विनियम प्रति की अनुलिपि प्रतियां जारी करने का आवेदन किया है। अपने तर्क के समर्थन में पार्टी ने स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस संख्या पी/ए/1400386 दिनांक 15-6-74 की मूल सीमाशुल्क प्रति तथा मुद्रा विनियम प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है तथा आदेश देता हूँ कि आवेदक को 2000 रुपये के लिए उक्त लाइसेंस संख्या पी/ए/1400386 दिनांक 14-6-74 की दोनों प्रतियां जारी की जानी चाहिए। अतः उक्त मूल लाइसेंस (दोनों प्रतियों) को रद्द किया जाता है।

[संख्या 12/395/74-75/एम एल-1/1319]

एन० शर्मा, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 8th March, 1976

S.O. 1314—M/s. Kumar Taxi, Palace road, Cochin were granted an Import Licence No. P/A/1400386 dated 15-6-74 for Rs. 2,000 only for the import of spares for tourist taxis covered by list II (part A & B) of Appendix 26 of the Red Book (Vol. I) for AM 74-75. The party has lost the licence (both copies) without having registered with any Customs authority & utilised at all. Now the party has applied for issue of duplicate copy of Customs copy & Exchange Copy of the said import licence. In support of this contention, the party has furnished an affidavit on the stamped paper. I am satisfied that the original Custom Copy & Exchange Copy of the import licence No. P/A/1400386 dated 15-6-74 has been lost/misplaced and direct that duplicate licence (both copies) of the said licence No. P/A/1400386 dated 15-6-74 for Rs. 2,000 should be issued to the applicant. The original licence (both copies) of the said licence are therefore cancelled.

[No. 12/395/74-75/ML. I/1319]

N. SHARMA, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1976

का० आ० 1315—सर्वश्री ब्रैक्स इन्डिया लि०, 37-माऊंट रोड, पेडे, मद्रास को एक जिनैल/विकस हाईनेस टेस्टिंग मशीन का आयात करने के लिए 34,152 रुपये (तीस हजार एक सौ बावन रुपये मात्र) का आयात लाइसेंस संख्या पी/सी/2066327/आर/के० के०/491एच-37-38/सी आई एल/ए/73(285)/जी ओ आई दिनांक 30-11-73 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस (सीमाशुल्क प्रयोजन तथा मुद्रा विनियम प्रयोजन प्रति) की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि आयात लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि आयात लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति किसी

भी सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत नहीं की गई थी तथा बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाई गई है।

2 अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी, मद्रास तमिलनाडु राज्य के समक्ष विधिवत् शपथ लेते हुए स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उक्त लाइसेंस संख्या पी/सी जी/2066327 दिनांक 30-11-1973 जो कि सर्वश्री ब्रेक्स इन्डिया लि०, मद्रास को जारी किया गया था, उसकी मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त आयात लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति तथा मुद्रा विनियम प्रयोजन प्रति की प्रतिलिपि पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या 7(55)/73-74/सी जी-1]

ORDER

New Delhi, the 20th March, 1976

S.O. 1315.—M/s. Brakes India Ltd., 37 Mount Road, Pade, Madras, were granted Import licence No. P/C/2066327/R/KK/49/H/37-38/CIL/A/73(285)/GOI dated 30-11-75 for Rs. 34,152 (Rupees Thirtyfour thousand one hundred and fifty two only) for import of One Number Brinell/Vickers Hardness Testing machine. They have applied for the import of a duplicate (Customs purposes and Exchange Control) copy of the said licence on the ground that the original customs purposes and Exchange Control copy of the import licence has been lost/misplaced. It has further been stated that original Customs purpose copy of import licence has not been registered with the Customs authorities and has not been utilized at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn before a Notary, Madras, Tamil Nadu State. I am accordingly satisfied that the original Customs purpose copy and Exchange control copy of the licence has been lost/misplaced. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Controls) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Customs purpose copy and Exchange Control copy of import licence No. P/CG/2666327 dated 30-11-1973 issued to M/s. Brakes India Limited., Madras, is hereby cancelled.

3. A duplicate customs purpose copy and exchange control copy of said import licence is being issued to the party separately.

[No. CG. 1/7(55)/73-74]

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1976

का० प्रा० 1316.—सर्वश्री हिन्दुस्तान फेरोडो लि०, बम्बई को 3,47,833 रुपये के लिए जो कि बाद में घटा कर 2,04,245 रुपये (दो लाख चार हजार दो सौ पैतालीस रुपये मात्र) कर दिया गया था, एक आयात लाइसेंस संख्या : पी/सीजी/2067019, दिनांक 27-3-74 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की प्रतिलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी बम्बई के पास पंजीकृत कराई गई थी तथा आंशिक रूप से उपयोग में लाई गई थी।

इसका उपयोग 41,5731 रुपये के लिए किया गया था तथा इसमें शेष धन 1,62,672 रुपये उपलब्ध था।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी, भारत सघ के समक्ष शपथ लेते हुए एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955, दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री हिन्दुस्तान फेरोडो लि०, बम्बई को जारी किए गए उक्त लाइसेंस संख्या पी/सीजी/2067019, दिनांक 27-3-74 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति एतद् द्वारा रद्द की गई है।

3. लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की प्रतिलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या : 92/74/34/सीजी-4]

चन्द्र गुप्त, उप-मुख्य नियंत्रक,

ORDER

New Delhi, the 22nd March, 1976

S.O. 1316.—M/s. Hindustan Ferodo Ltd., Bombay were granted an import licence No. P/CG/2067019 dated 27-3-74 for Rs. 3,47,833, which was later on reduced to Rs. 2,04,245 (Rupees two lakhs, four thousand, two hundred and forty-five only). They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes Copy of the said import licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes Copy was registered with the Customs Authorities at Bombay and utilised partly. It was utilised for Rs. 41,573 and the balance available on it was Rs. 1,62,672.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit sworn before a Notary, Union of India. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes Copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955, dated 7-12-1955 as amended, the said original Customs Purposes Copy of licence No. P/CG/2067019 dated 27-3-74 issued to M/s. Hindustan Ferodo Ltd., Bombay, is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes Copy of the said licence is being issued separately to the licencee.

[No. 92/74/34/CG. IV]

CHANDRA GUPTA, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1976

का० प्रा० 1317.—सर्वश्री इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि०, हिमालय हाउस (दूसरी मंजिल) 23 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को 25,550 रुपये (पच्चीस हजार पांच सौ पचास रुपये मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या आई/सी/2069824/एस/एफ ई/55/एच/41-42/सी जी. 2, दिनांक 25-7-75 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की प्रतिलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं की गई है तथा उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी, दिल्ली के समक्ष विधिवत् शपथ लेते हुए एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9

(सीसी) के प्रतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उक्त लाइसेंस संख्या आई/सी/2069824/एस/एफ 5/55/एच/41-12/सी जी-2, दिनांक 25-7-1975 जो कि सर्वश्री इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०, हिमालय हाउस (दूसरी मंजिल) 23-कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को जारी किया गया था, इसकी मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एतद द्वारा रद्द की जाती है।

साइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रलग से जारी की जारी रही है।

[संख्या सी जी 2/पी एण्ड सी/157/74-75/2274]

ORDER

New Delhi, the 22nd March, 1976

S.O. 1317.—M/s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Himalaya House (2nd Floor), 23-Kasturba Gandhi Marg, New Delhi were granted an Import Licence No. I/C/2069824/C/FE/55/H/41-42/CG. II dated 25-7-75 for Rs. 25,500 (Rupees twenty five thousand and five hundred only). They have applied for the issue of a duplicate customs purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes Copy has not been registered with any Customs Authority and not utilised at all.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before the Notary, Delhi. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes Copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) order 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Customs Purposes Copy of the Licence No. I/C/2069824/S/FE/55/H/41-42/CG. II dated 25-7-1975 issued to M/s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Himalaya House (2nd Floor), 23-Kasturba Gandhi Marg, New Delhi is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. CG. II/P&C/157/74-75/2274]

आवेद

का०प्रा० 1318.—सर्वश्री इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०, हिमालय हाउस (दूसरी मंजिल) 23-कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को 75,52,102 रुपये (पचहत्तर लाख, बावन हजार, एक सौ दो रुपये मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या आई०/सी/2070085/सी/एक्स एक्स/56/एच/41-42/सी जी 2, दिनांक 3-9-1975, प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थायित्व हो गई है। प्रागे यह भी बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं की गई है तथा उसका बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी दिल्ली के समक्ष विधिवत शपथ लेने हुए एक शपथपत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। अतः संशोधित आयात (नियंत्रण) आवेद 1955, दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सी सी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उक्त लाइसेंस संख्या आई/सी/2070085/सी/एक्स एक्स/56/एच/41-42/सी जी 2, दिनांक 3-9-1975 जो कि सर्वश्री इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०, हिमालय हाउस (दूसरी मंजिल), 23-कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को जारी किया गया था, उसकी मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति एतद द्वारा रद्द की जाती है।

लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रलग से जारी की जा रही है।

[संख्या सी जी 2/पी एण्ड सी/79/75-76/2275]

एन० सी० काजीलाल, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

S.O. 1318.—M/s. Indian Petrochemicals Corporation Limited, Himalaya House (2nd Floor), 23-Kasturba Gandhi Marg, New Delhi were granted an Import Licence No. I/C/2070085/C/XX/56/H/41-42/CG. II dated 3-9-1975 for Rs. 75,52,102 (Rupees seventy five lakhs fifty two thousand one hundred and two only). They have applied for the issue of a duplicate customs purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes Copy has not been registered with any Customs Authority and not utilised at all.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before the Notary, Delhi. I am accordingly satisfied that the original customs purposes copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Customs Purposes Copy of the licence No. I/C/2070085/C/XX/56/H/41-42/CG. II dated 3-9-1975 issued to M/s. Indian Petrochemicals Corporation Limited, Himalaya House (2nd floor), 23-Kasturba Gandhi Marg, New Delhi is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. CG. II/P&C/79/75-76]

N. C. KANJILAL, Dy. Chief Controller

आवेद

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1976

का०प्रा० 1319.—वि प्रोजेक्ट एंड एक्विपमेंट्स कारपोरेशन आर इंडिया लि०, नई दिल्ली को पश्चिमी जर्मनी से 7,00,000 रुपये मूल्य तक कालर ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस संख्या जी/टी/2411436, दिनांक 29-7-1975 प्रदान किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उनसे उपर्युक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है। लाइसेंसधारी ने प्रागे यह भी बताया है कि लाइसेंस भारत के किसी भी पक्ष पर पंजीकृत नहीं हुआ है।

आवेदक ने अपने तर्क के समर्थन में एक शपथपत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या जी/टी/2411436, दिनांक 29-7-1975 की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति उनको जारी की जाए। लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति द्वारा रद्द की जाती है।

लाइसेंस संख्या: जी/टी/2411436/दिनांक 29-7-75 की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति प्रलग से जारी की जा रही है।

[संख्या एस टी सी/कैन-74/75-76/भार एम सैल/3060]

जी० एस० ग्रेवाल, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 23rd March, 1976

S.O. 1319.—The Projects & Equipments Corporation of India Ltd., New Delhi were granted licence No. G/T/

2411436 dated 29-7-75 for the import of Spares for Crawler Tractors from West Germany to the value of Rs. 7,00,000. They have requested for the issue of duplicate Exchange Control copy of the above licence on the ground that the Original Exchange Control Copy of the above licence has been lost by them. It has been further reported by the licensee that the licence has not been registered with any port in India.

In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that Exchange Control copy of licence No. G/T/2411436 dated 29-7-75 has been lost and direct that Exchange Control copy of the said licence should be issued to them. The Exchange Control copy of the licence is hereby cancelled.

Exchange control copy of the licence No. G/T/2411436 dated 29-7-75 is being issued separately.

[F No. STC/Can-74/75-76/RM Cell/3060]

G. S. GREWAL, Dy. Chief Controller

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय

लौह और इस्पात प्रभाग

आदेश

कलकत्ता, 29 जनवरी, 1976

कां०आ० 1320—सर्वश्री हिन्दुस्तान स्टील लि०, 2, फेयरलाई प्लेस कलकत्ता-1 को 1971-72 की अवधि के लिए निम्नलिखित आयात लाइसेंस प्रदान किया गया था और कथित लाइसेंस के लिए प्राधिकार पत्र, सर्वश्री लिड्ज एण्ड कन्टेनर्स 596/3, डायमण्ड हारबर रोड, बिहाला, कलकत्ता-34 के नाम में जारी किया गया था।

आयात लाइसेंस संख्या और तिथि विवरण मूल्य
पी/एस/8222468/सी/एक्सएक्स/51/सी टिनप्लेट वेस्ट वेस्ट 5000 रुपए]
33-34/01/198 दिनांक
28-6-74

प्राधिकार पत्र के धारक सर्वश्री लिड्ज एण्ड कन्टेनर्स कलकत्ता-34 ने 5000 रुपए के पूरे मूल्य के लिए उपर्युक्त आयात लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए आवेदन किया है। चूंकि उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत कराये बिना और उसका कोई भी भाग उपयोग किए बिना ही खो गई है। कुल धनराशि जिसके लिए उपर्युक्त लाइसेंस प्रदान किया गया था। वह 5000 रुपए है और कुल धनराशि जिसके लिए मूल प्रति उपयोग में लाई गई थी वह "शून्य" है। अब उन्हें सम्पूर्ण मूल्य अर्थात् 5000 रुपए को पूरा करने के लिए अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति की आवश्यकता है।

2. अपने इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट बस्तीपुर, 24-मरगना द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

3. मैं संतुष्ट हूँ कि आयात लाइसेंस संख्या पी/एस/8222468/सी/एक्सएक्स/51/सी/33-34/01/198 दिनांक 28-6-74 की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता हूँ कि आवेदक को पूरे मूल्य अर्थात् 5000 रुपये के लिए आयात लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिए।

[संख्या : जे सी/आर्० एण्ड ० एस/II/01/198/72/1787]

आर० सी० एस० मेनन, उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

(Iron & Steel Divn.)

ORDER

Calcutta, the 29th January, 1976

S.O. 1320.—M/s. Hindustan Steel Ltd, 2, Fairlie Place, Calcutta-1 were issued "the Import Licence for the period 1971-72" as under and Letter of Authority against the said Import Licence was issued in favour of M/s. Lids & Containers, 596/3, Diamond Harbour Road, Behala, Calcutta-34:

Import Licence No & Date	Description	Value
P/S/8222468/C/XX/51/ C/33-34/01/198 dt. 24-6-74	Tinplate waste Waste	Rs. 5000/-

The Letter of Authority holder, M/s. Lids & Containers, Calcutta-34 have applied for the duplicate Exchange Control Purposes Copy of the above quoted Import Licence for the full value of Rs. 5,000 since they have confirmed that the Exchange Control Purposes copy of the above licence has been lost without having been registered with any Customs House and without utilising any part. The total amount for which the above Licence was issued is Rs. 5,000 and the total amount for which the original copy was unutilised is "Nil". The duplicate Exchange Control Purposes copy now required it to cover the entire amount of Rs. 5,000.

2. In support of this contention of the applicant has filed an "Affidavit" on a stamped paper duly attested by the Executive Magistrate, Alipore, 24 Parganas.

3. I am satisfied that the Exchange Control Purposes copy of the Import Licence No P/S/8222468/C/XX/51/C/33-34/01/198 dated 28-6-74 has been lost and direct that the duplicate Exchange Control Purposes copy of the Import Licence for full value of Rs. 5,000/- should be issued to the applicant. The Exchange Control Purposes copy of the above Import Licence is cancelled for the amount of Rs. 5,000.

[No. JC/I&S/II/01/198/72/1787]

R. C. S. MENON, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1976

कां०आ० 1321—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, मलाया-कोयासी/मथुरा पाइप लाइन प्रोजेक्ट, "डोली"-33बी, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी निधि व्यवसायी की माफ़त।

the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B, Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka: Rajkot District: Rajkot Gujarat State

Village	Survey No.	Extent		
		HA	Sq.	M
Gavaridad	22	0	29	20
	18	0	17	05
	19	0	24	60
	199 P	0	12	70
	198/1	0	15	10
	197 P	0	15	15
	204/1	0	01	10
	511/P 1	0	12	35
	511/P 2	0	10	15
	180/1-P-1	0	34	65
	180/1-P-2	0	01	40
	181	0	57	25
	183	0	31	65
	185 P	0	31	00
	193	0	01	20
	170	0	23	25
	168	0	47	70
	166	0	12	35
	167	0	30	55
	164	0	15	90
	163	0	23	50
Rajgadth	157	0	29	55
	241	0	30	25
	16	0	16	65
	23	0	19	30
	22	0	19	30
	32 P 1	0	13	00
	32 P 2	0	16	80
	32 P 3	0	15	

[No. 12017/6/74-L&L]

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1976

का० आ० 1322.—यतः पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 3234 तारीख 19-11-1974 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जन करने का अपना आशय घोषित किया था।

अतः मन्त्रम प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 6 उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1547 दिनांक 2-5-1975 में प्रथम उल्लिखित अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित किया गया तथा निदेश दिया गया कि ऐसा अर्जित किया गया अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में निहित होगा।

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

Now Delhi, the 23rd March, 1976

S. O. 1321.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), 2 GI/76—4.

[संख्या 12017/6/74 एल० एण्ड एल०]

और अतः तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त भूमि के उपयोग के अधिकार के ह्याग का निश्चय किया ;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रथम उल्लिखित अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अर्जित भूमियों के उपयोग के अधिकार का ह्याग करती है, तथा उपरोक्त अधिसूचना सं० का०प्रा० 3234 तथा का०प्रा० 1547 दिनांक क्रमशः 19 नवम्बर, 1974 और 2 मई, 1975 को रद्द करती है।

[सं० 12016/10/74-एल एण्ड एल/III]

टी०पी० सुब्रह्मनियन, भवर सचिव

New Delhi, the 25th March, 1976

S.O. 1322.—Whereas by a notification S.O. No. 3234 dated 19-11-1974 made under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) had declared its intention to acquire the right of user in respect of the lands specified in the Schedule appended to that notification, for the purpose of laying pipeline.

And whereas, after considering the report of the competent authority, the Central Government in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) by notification No. S.O. 1547 dated 2-5-1975, made under sub-section (1) section 6 of the said Act, acquired the right of user in respect of the lands specified in the Schedule appended to the first-mentioned notification and further directed that the right of user so acquired shall, instead of vesting in the Central Government, vest in the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas the Central Government has, on the recommendation of the Oil & Natural Gas Commission, decided to relinquish the right of user in respect of the aforesaid land ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, the Central Government hereby relinquished the right of user which was acquired in respect of the lands specified in the Schedule to the first-mentioned notification and rescinds the aforesaid notification Nos. S.O. No. 3234 and S.O. No. 1547, dated, the 19th November, 1974 and 2nd May, 1975 respectively.

[No. 12016/15/74-L&L-III]

T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1976

का०प्रा० 1323.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती तथा यह निदेश करती है कि उक्त अधिकारी, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा-अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का नाम	सरकारी स्थान
(1)	(2)
श्री सी०एन० सुब्रह्मन्यन, भवर सचिव उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग	उद्योग भवन

[फा०सं० डी-11012/12/73-जी०ए०]

ऐ० महादेवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 23rd March, 1976

S. O. 1323:—In exercise of the powers conferred by sections 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act., 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoint the officer mentioned in column (1) of the Table below being Gazetted Officer of Government to be estate officer for the purpose of the said Act, and further directs that the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officer by or under the said Act in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Name of officer	Public Premises
(1)	(2)
Shri C. N. Subramanian Under Secretary, Ministry of Industry and Civil Supplies Department of Industrial Development	Udyog Bhawan.

[File No. D-11012/12/73-G.A.]

I. MAHADEVAN, Joint Secy.

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1976

क्र० आ० 1324.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार और IS: 1448 (पी० 82) — 1974 पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुओं की परीक्षण पद्धतियाँ : आयोडीन मोनोक्लोराइड पद्धति द्वारा गैसोलिन में सीसे की कुल मात्रा ज्ञात करने की पद्धति के प्रकाशन के फलस्वरूप अधिसूचित किया जाता है कि IS: 1448 (पी० 37) पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुओं की परीक्षण पद्धतियाँ : क्लोरेट आक्सीकरण पद्धति द्वारा टेट्रोइथाइल सीसा की परीक्षण पद्धति (टी०ई०एल०) (पहला पुनरीक्षण) नामक भारतीय मानक जिसके ब्यौरे भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 10 फरवरी 1968 में अधिसूचना संख्या एस० 520 दिनांक 25 जनवरी, 1968 के अंतर्गत छपे थे, अब वापस ले लिया गया है और वह रद्द माना जाए।

[संख्या सी०एम०डी०/13:7]

ए० बी० राव, उप महानिदेशक

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 22nd March, 1976

S- O- 1324—In pursuance of sub-regulation (1) of regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation 1955, has amended from time to time and consequent upon publication of IS:1448(P:82)—1974 Methods of test for petroleum and its products: total lead content in gasoline by iodine monochloride method, it is, hereby, notified that IS:1448 (P:37)—1967 Methods of test for petroleum and its products: tetraethyl lead (TEL) by chlorate oxidation method (first revision) details of which were published under notification number S. O. 520 dated 25 January 1968, in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 10 February, 1968, has been withdrawn and stands cancelled.

[No. CMD/13:7]

A. B. RAO, Dy. Dir. General.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1976

क्र० आ० 1325 समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 3 के उपविनियम (4) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अनुसार IS: 1848-1971 के उपबंधों में कुछ संशोधन जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए हैं, मानक चिन्ह के उपयोग में गति लाने के लिए परीक्षात्मक रूप में किए गए हैं। इन संशोधनों से भारतीय मानक के अधीन आने वाले माल की गुणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अधिसूचना 22 मार्च 1976 से लागू होगी :

अनुसूची

क्रम भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक जिसके उपबंधों में संशोधन किया गया भारतीय मानक के उपबंधों में किए गए संशोधनों का विवरण संख्या है

(1)	(2)	(3)
1. IS: 1848-1971 लिखने और छपाई के कागज की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन की भूमिका.— उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय भारत सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि शिक्षा तथा सरकारी कार्यों के लिए छपाई का सफेद कागज सैयार करने वाली मिलों द्वारा इस कागज पर 0.005 प्रतिशत भस्मीय हरे रंग की रंगत दी जाए। चूंकि इस प्रकार के कागज पर भारतीय मानक संस्था प्रमाणन मुहर लगाना अनिवार्य है अतः रंगत देने सम्बन्धी प्रपेक्षा की भारतीय मानक में व्यवस्था करनी आवश्यक है :	(पृष्ठ 4, खण्ड 3.7) खण्ड 3.6 के भाव बिम्बलिखित जोड़ लीजिए : '3.7 छपाई के सफेद कागज (देखिए क्रम संख्या xvii सारणी 1) में कोई रंगत भी हो सकती है। ऐसे कागज की रंगत उस रंग की मात्रा के निकटतम होनी चाहिए जिसका समय-समय पर संस्था द्वारा अनुमोदन किया गया हो। रंगत वाले छपाई के इस कागज के लिए भस्म सम्बन्धी प्रपेक्षाएं लागू नहीं होती।'

[सी०एम०डी०/13:4]

बी०एस० कुणामाचार, महानिदेशक

New Delhi, the 24th March, 1976

S. O. 1325.—In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation (4) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, modifications to the provisions of IS:1848-1971, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have tentatively been made with a view to expediting the use of the Standard Mark, without any way affecting the quality of goods covered by the relevant standard. This notification shall come into force with effect from 22nd March, 1976.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of Indian Standard the Provisions of which have been modified	Particulars of the Modifications made to the provision.
1.	IS:1848-1971: Specification for writing and printing papers (first revision)	<p>Foreword to amendment</p> <p>The Government of India, Ministry of Industry and Civil Supplies has made it obligatory that the paper mills producing white printing paper for educational and Government purposes shall tint the paper with 0.005 percent of brilliant green dye. It is necessary to include this provision of tinting in the Indian Standard in view of the compulsory ISI Certification Marking for this type of paper.</p> <p>(Page 4, clause 3.7)—Add the following after 3.6:</p> <p>‘3.7 white printing paper see Sl. No. XVII of Table 1) may also be tinted. In the case of tinted paper the colour shall be close Match to the shade approved by the Institution from time to time. The requirement of brightness shall not apply in the case of printing paper so tinted.’</p>

[No. CMD/13:4]

B.S. Krishnaamchar, Director, General

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1976

का० घ्रा० 1326.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, (ii), तारीख 2 अगस्त, 1975 में का० घ्रा० 2474 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० 48013(10)/73-मेटल्स-iii तारीख 5 जुलाई, 1975 में पृष्ठ 2876—79 सारणी के स्तम्भ (1) के अधीन दिए गए श्री० के० के० विद्यार्थी के पदाभिधान, “कार्मिक और प्रशासनिक अधिकारी” के स्थान पर, “कार्मिक और प्रशासनिक प्रबंधक” पढ़ें।

[का० सं० 48013/10/73-मेटल्स-iii]

सी०पी०एम० नायर, उप सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1976

का० घ्रा० 1327.—विद्युत (प्रवाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54वां) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या बिजली-दो-28(8)/72, दिनांक 23 फरवरी, 1976 में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नियम करती है कि प्रसंख्या 5 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

“श्री के०पी० तैमनी,

सदस्य,

(आर्थिक और वाणिज्यिक), केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण।”

[संख्या बिजली-दो-28(8)/72]

सुरेन्द्र प्रकाश जैन, उप निदेशक

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th March, 1976

1326.—In the Government of India the Ministry of Steel & Mines (Department of Mines) Notification No. 48013/10/73-Met. III dated 5th July, 1975, published in Part II Section 3(ii) of the Gazette of India dated 2nd August, 1975 as S.O. 2474 at pages 2880-2881, for the designation of Shri K. K. Vidyarthi given under col. (1) of the table as “Personnel and Administrative Officer” read “Personnel and Administrative Manager”.

[F. No. 48013/10/73-Met. III]

C. P. S. NAIR, Dy. Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

New Delhi, the 25th March, 1976

S.O. 1327.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) and in partial modification of this Ministry's Notification No. EL. II-28(8)/72 dated the 23rd February, 1976, the Central Government hereby decides that after serial No. 5 thereof the following may be inserted:

“6. Shri K. P. Taimni,
Member,
(Economic and Commercial).
C.E.A.”

[No. EL. II-28(8)/72]

S. P. JAIN, Dy. Director

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1976

क्रा०प्रा० 1328—यत् भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्ति उनके नाम के आगे विनिर्दिष्ट किये गए विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक के मामले उल्लिखित तिथि में भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य निर्वाचित किये गये हैं नामतः—

व्यक्ति का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	निर्वाचन तिथि
डा० वी०एस० वेकट सुब्बु प्रधानाचार्य, एम०बी० मेडिकल कालेज, तिरुपति ।	श्री वेकटेश्वर विश्व-विद्यालय	20-12-1975
डा० पी०सी० बंसल डीन, मेडिकल कालेज औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	मराठवाडा विश्वविद्यालय	7-9-1975
डा० राधानाथ राठ प्रधानाचार्य, एम०के०सी०जी० मेडिकल कालेज, बेरहामपुर	बेरहामपुर विश्वविद्यालय	25-9-1975
डा० एम०पी० वैद्य, प्रधानाचार्य, हिमाचल प्रदेश मेडिकल कालेज, शिमला तथा डीन, आयुर्विज्ञान संकाय	हिमाचल प्रदेश विश्व-विद्यालय	15-7-1975
डा० एम०एन० अहमद शाह डीन, औषधि संकाय तथा प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, श्रीनगर	कश्मीर विश्वविद्यालय	22-2-1975

अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उसके द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/59-वि० में आगे और निम्नलिखित सशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत निर्वाचित" शीर्षक के अधीन—

(i) क्रम संख्या 14, 23, 39 और 47 तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएँ तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेगी, नामतः—

"14. डा० वी०एस० वेकट सुब्बु प्रधानाचार्य, एम०बी० मेडिकल कालेज, तिरुपति

23. डा० पी०सी० बंसल डीन, मेडिकल कालेज, औरंगाबाद महाराष्ट्र

39. डा० राधानाथ राठ, प्रधानाचार्य, एम०के०सी०जी० मेडिकल कालेज, बेरहामपुर

47. डा० एम०पी० वैद्य, प्रधानाचार्य, हिमाचल प्रदेश मेडिकल कालेज, शिमला तथा डीन, आयुर्विज्ञान संकाय"

(ii) क्रम संख्या 50 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जायेगी, नामतः—

"51 डा० एम०एन० अहमद कश्मीर विश्वविद्यालय
शाह डीन, औषधि संकाय
तथा प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट
मेडिकल कालेज, श्रीनगर

[म० वी० 11013/1/75 एम.पी.टी.]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 20 March, 1976

S.O. 1328 :—Whereas in pursuance of Clause (b) of sub-section (i) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the following persons have been elected by the University, specified against each of them to be members of the Medical Council of India with effect from the date noted against each, namely:—

Name of the person	Name of the University	Date of election
Dr. V. S. Venkata Subbu, Principal, S. V. Medical College, Tirupatti.	Sri Venkateswara University	20-12-1975
Dr. P. C. Bansal, Dean, Medical College, Aurangabad (M. S.)	Marathwada University	7-9-1975
Dr. Radhanath Rath, Principal, M. K. C. G. Medical College, Berhampur.	Berhampur University	25-9-1975
Dr. M. P. Vaidya, Principal, H. P. Medical College, Simla and Dean, Faculty of Medical Science.	Himachal Pradesh University	15-7-1975
Dr. S. N. Ahmad Shah, Dean, Faculty of Medicine & Principal, Government Medical College, Srinagar.	University of Kashmir	22-2-1975

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 5-13/59-MI, dated the 9th January, 1960, namely:—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3";

(i) for serial numbers 14, 23, 39 and 47 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall respectively be substituted namely:—

"14 Dr. V. S. Venkata Subbu, Principal, S. V. Medical College, Tirupatti.

23. Dr. P. C. Bansal, Dean, Medical College, Aurangabad (M. S.)

39. Dr. Radhanath Rath, Principal, M. K. C. G. Medical College, Berhampur

47. Dr. M. P. Vaidya, Principal, Himachal Pradesh Medical College, Simla and Dean, Faculty of Medical Science"

(ii) after serial number 50 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

"51. Dr. S. N. Ahmad Shah, Dean, University of Kashmir Faculty of Medicine, and Principal, Government Medical College, Srinagar."

[No. V. 11013/1/75-MPT]

का० प्रा० 1329.—भारतीय चिकित्सा परिषद नियमावली, 1957 के नियम 2 के खण्ड (घ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा केरल के चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार श्री पी० के० परमेश्वरन नायर को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन केरल राज्य में भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य का निर्वाचन कराने के लिये निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करती है।

[सं० बी० 11013/1/76-एम पी टी]

S.O. 1329.—In pursuance of clause (d) of rule 2 of the Indian Medical Council Rules, 1957, the Central Government hereby appoints Shri P. K. Parameswaran Nair, Registrar of Medical Council, Kerala, as Returning Officer for the conduct of election of a member to the Medical Council of India under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) in the State of Kerala.

[No. V. 11013/1/76-MPT]

का० प्रा० 1330.—यतः दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड (ड) के उपबन्धों के अनुसरण में असम सरकार ने स्वास्थ्य सेवा असम के अपर निदेशक डा० पी० बोरा को 4 दिसम्बर 1974 से भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद का सदस्य मनोनीत किया किया है।

अब यतः उक्त अधिनियम की धारा 3 का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की 17 अक्टूबर 1962 की अधिसूचना संख्या 3-2/62-चिकि० 2 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, "भाग 3 के खण्ड (ड) के अधीन मनोनीत शीर्ष में" क्रम संख्या 2 के समक्ष, वर्तमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाएगी:—

"डा० पी० बोरा,
स्वास्थ्य सेवा के अपर निदेशक,
गोहाटी, असम।"

[संख्या बी०-12013/1/76-एम पी टी]

S.O. 1330.—Whereas the Government of Assam has, in pursuance of the provisions of clause (c) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), nominated Dr. P. Bora, Additional Director of Health Services, Assam, to be a member of the Dental Council of India, with effect from the 4th December, 1974;

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning No. 3-2/62-MII dated the 17th October 1972, namely:—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (c) of section 3", against serial No. 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Dr. P. Bora,
Additional Director of Health Services,
Gauhati, Assam."

[No. V. 12013/1/76-MPT]

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1976

का० प्रा० 1331.—यतः केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के उपबन्धों के अनुसरण में डा० पी० पी० गोयल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली को 3 मार्च 1976 से भारतीय चिकित्सा परिषद का सदस्य मनोनीत करती है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की तारीख 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/58-एम० 1 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, "खण्ड 3 के उप-खण्ड (i) के क्वाज (ड) के अधीन मनोनीत" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 8 के समक्ष मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, अर्थात् —

"डा० पी० पी० गोयल,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक
नई दिल्ली।"

[संख्या बी० 11013/2/76-एम पी टी]

एस० श्री निवासन, उप सचिव

New Delhi, the 22nd March, 1976

S.O. 1331.—Whereas the Central Government have, in pursuance of the provisions of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956, nominated Dr. P. P. Goel, Director General of Health Services, New Delhi, to be a member of the Medical Council of India, with effect from the 3rd March, 1976;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Planning No. 5-13/58-M 1, dated the 9th January 1960, namely:—

† In the said notification, under the heading "nominated under clause (c) of sub-section (i) of section 3", against serial No. 8, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Dr. P. P. Goel,
Director General of
Health Services,
New Delhi."

[No. V. 11013/2/76-MPT]

S. S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

नौबत और परिवर्तन मंत्रालय

(परिवर्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1976

का० प्रा० 1332.—कलकत्ता डाक कमिश्नर (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप, डाक कमिश्नर (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित

भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मन्त्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 4708 तारीख 16 अक्तूबर, 1975 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 1 नवम्बर, 1975 में पृष्ठ 3895 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र 17 नवम्बर, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था; और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता डाक कर्मचार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का नाम, कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) तृतीय संशोधन स्कीम, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है), जब तक कि अन्यथा स्पष्टतः उपबन्धित न किया गया हो, "कलकत्ता पत्तन आयुक्त" और "पत्तन आयुक्त" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आए हों, "कलकत्ता पत्तन न्यास" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त स्कीम की अनुसूची vi में उपबन्धित कलकत्ता पत्तन के डाक कर्म कारों के लिए प्रस्तावित स्कीम के खण्ड 9 के उपखण्ड (iii) की मध (क) में "कलकत्ता पत्तन आयुक्त के कर्मचारी वृन्द" शब्दों के स्थान पर "कलकत्ता पत्तन न्यास के कर्मचारीवृन्द" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० एलजीसी/27/75-1]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 24th March, 1976

S.O. 1322.—Whereas certain draft Scheme further to amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), at page 3895 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st November, 1975 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 4708, dated the 16th October, 1975, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of sixty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 17th November, 1975;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Calcutta Dock Workers, (Regulation of Employment) Scheme, 1970, namely :—

1. This Scheme may be called the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Third Amendment Scheme, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Throughout the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the said Scheme), unless otherwise expressly provided, for the words "Calcutta Port Commissioners" and "Port Commissioners", wherever they occur, the words "Calcutta Port Trust" shall be substituted.

3. In item (a) of sub-clause (iii) of clause 9 of the Incentive Scheme for Dock Workers of the Port of Calcutta set out in Schedule VI to the said Scheme, for the words "Calcutta Port Commissioners' staff", the words "Calcutta Port Trust's staff" shall be substituted.

[No. IDC/27/75-1]

का० प्रा० 1333.—कलकत्ता डाक लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने लिए स्कीम का एक प्रारूप, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मन्त्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 4710 तारीख 16 अक्तूबर, 1975 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii), तारीख 1 नवम्बर, 1976 में पृष्ठ 3896 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र 17 नवम्बर, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था।

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता डाक लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इस स्कीम का नाम कलकत्ता डाक लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) तृतीय संशोधन स्कीम, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कलकत्ता डाक लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है), जब तक कि अन्यथा स्पष्टतः उपबन्धित न किया गया हो, "कलकत्ता पत्तन आयुक्त" और "पत्तन आयुक्त" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आए हों, "कलकत्ता पत्तन न्यास" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त स्कीम की अनुसूची iii के खण्ड 3 के उपबन्ध (च) में, "पत्तन आयुक्त के सौंड लिपिक" शब्दों के स्थान पर "कलकत्ता पत्तन न्यास के सौंड लिपिक" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० एलजीसी/27/75 II]

S.O. 1333.—Whereas certain draft Scheme further to amend the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, was published as required by sub-section (1) of Section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), at page 3896 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st November, 1975, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 4710, dated the 16th October, 1975, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 17th November, 1975;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, namely :—

1. This Scheme may be called the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment), Third Amendment Scheme, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Throughout the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, (hereinafter referred to as the said Scheme), unless otherwise expressly provided, for the words "Calcutta Port Commissioners" and "Port Commissioners", wherever they occur, the words "Calcutta Port Trust" shall be substituted.

3. In sub-clause (f) of clause 3 of Schedule III to the said Scheme, for the words "Port Commissioners" "Shed Clerks" the words "Calcutta Port Trust's Shed Clerks" shall be substituted.

[LDC-27/75-II]

का० आ० 1334.—कलकत्ता छीलन तथा रंग रोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन), अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के तौरहून और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० आ० 4709, तारीख 16 अक्तूबर, 1975 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 1 नवम्बर, 1975 में पृष्ठ 3895 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी;

और उक्त राजपत्र 17 नवम्बर, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था,

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है,

अतः, अध, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता छीलन तथा रंग रोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का नाम कलकत्ता छीलन तथा रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन), तृतीय संशोधन स्कीम, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कलकत्ता छीलन तथा रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन), स्कीम, 1970 में, "कलकत्ता पत्तन आधुनिक" शब्दों के स्थान पर, जहाँ कहीं भी वे आए हों, "कलकत्ता पत्तन व्याप" शब्द रखे जाएंगे।

[स० एन डी नो/27/75-3]

बी० सकारालिंगम, अरर मन्त्र, (एन)

S.O. 1334—Whereas certain draft Scheme further to amend the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, was published as required by sub-section (1) of Section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), at page 3896 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st November, 1975, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 4709, dated the 16th October, 1975, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 17th November, 1975;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, namely :—

1. This Scheme may be called the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment), Third Amendment Scheme, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Throughout the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, for the words "Calcutta Port Commissioners", wherever they occur, the words "Calcutta Port Trust" shall be substituted.

[LDC-27/75-III]

V. SANKARALINGAM, Under Secy. (L)

संचार सत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1976

का० आ० 1335.—ग्रोवाबाद टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी जानकारी के लिए, जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434 (III) (बोडी) में अपेक्षित है। ग्रोवाबाद में चालू समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों, तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें-

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 13 अक्तूबर, 1975 को दैनिक "मारुवाड़ा", "अजन्ता" और "लोकविजय" समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी;

उक्त सूचना के उत्तर में जनसाधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए ;

इसलिए अब उक्त नियमावली के नियम 434(III)(बीबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, डाक तार ने घोषित किया है कि तारीख 1-5-1976 से औरंगाबाद का स्थानीय संगोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

औरंगाबाद टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था:—

औरंगाबाद का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जोकि औरंगाबाद टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि०मी० की दूरी के अन्तर्गत पड़ता है ; किन्तु वे टेलीफोन उपभोक्ता जो कि औरंगाबाद नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित हैं, किन्तु जिन्हें औरंगाबाद टेलीफोन व्यवस्था से सेवा प्रदान होती है, वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 कि०मी० दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तक तब स्थानीय शुल्क वर से आदायगी करेंगे ।

[सं० 3-8/74 पी० एच० बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 24th March, 1976

S.O. 1335.—Whereas a public notice for revising the local area of Aurangabad Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Aurangabad, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas the said notice was made available to the public on 10th October, 1975 in daily Newspapers : 'Marthwada', 'Ajanta' and 'Lokvijay' ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-5-1976 the revised local area of Aurangabad shall be as under :—

Aurangabad Telephone Exchange System—

The local area of Aurangabad shall cover an area falling under the jurisdiction of Aurangabad Municipality :

Provided that the telephone subscribers located outside Aurangabad Municipal limit but who are served from Aurangabad Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-8/74-PHB]

का० आ० 1336.—चिकलथाना टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक सर्वसाधारण सूचना उन सबकी 2 GI/76—5

जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434 (III) (बीबी) में अपेक्षित है चिकलथाना में चालू समाचार पत्रों में निकासी गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या कोई सुझाव हों तो वे इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें,

उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 13 अक्टूबर, 1975 को दैनिक "मारव्वाडा", "अजन्ता" और "लोकविजय" समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी,

उक्त सूचना के उत्तर में जन साधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए ;

इसलिए अब डाक नियमावली के नियम 434(III) (बी बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, डाक तार ने घोषित किया है, कि तारीख 1-5-1976 से चिकलथाना का स्थानीय संगोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा—

चिकलथाना टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था:—

चिकलथाना का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जोकि चिकलथाना टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि०मी० की दूरी के अन्तर्गत पड़ता है :

किन्तु यह सीमा पश्चिम में औरंगाबाद नगरपालिका सीमा तक प्रतिबंधित होगी ।

[सं० 3-8/74-पी० एच० बी०]

पी० एन० कौल, निदेशक

S.O. 1336.—Whereas a public notice for revising the local area of Chikalthana Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Chikalthana inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas the said notice was made available to the public on 13th October, 1975 in daily Newspapers ; 'Marathwada', 'Ajanta' and 'Lokvijay' ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434(III)(bb) of the said Rules, the Director General, Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-5-1976 the revised local area of Chikalthana shall be as under :—

Chikalthana Telephone Exchange System—

The local area of Chikalthana shall cover an area falling within 5 Kms. radial distance from the Chikalthana Telephone Exchange :

Provided that in the West this limit shall be restricted to the boundary of Aurangabad Municipality.

[No. 3-8/74-PHB]

P. N. KAUL, Director

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1976

का० आ० 1337.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने फरीदकोट टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-5-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निर्णय किया गया है।

[सं० 5-7/76-पी०एच०बी०]

पी० सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक

New Delhi, the 25th March, 1976

S.O. 1337.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-5-1976 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Faridkot Telephone Exchange, N.W. Circle.

[No. 5-7/76-PHB]

P. C. GUPTA, Asstt. Director General.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च, 1976

का० आ० 1338.—वायु निगम अधिनियम, 1953, (1953 का 27) की धारा 4 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना सं० ए०बी० 18013/4/75-ए०सी०, दिनांक 13-2-1976 में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा एकीकृत वित्त सलाहकार श्री बाबलराय को तत्काल, तथा अगले आदेशों तक, श्री एम० वासुदेवन के स्थान पर एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडलों में एक निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० ए० बी० 18013/4/75-ए०सी०]

[सी० एल० दींगरा, उप सचिव]

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 23rd March, 1976

S.O. 1338.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Air Corporations Act, 1953 (2 of 1953) and in partial notification of the Notification No. Av. 18013/4/75-AC, dated 13-2-1976, the Central Government hereby appoints Shri Badal Roy, Joint Secretary and Integrated Financial Adviser, Ministry of Tourism & Civil Aviation as a Director on the Boards of Air India and Indian Airlines in place of Shri S. Vasudevan, with immediate effect and until further orders.

[No. A.V. 18013/4/75-AC]

C. L. DHINGRA, Dy. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1976

का० आ० 1339.—यस: केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11-क के अन्तर्गत दिल्ली की वृहत्त योजना में रिहायशी प्लॉटों पर लागू होने वाले जोनिंग रेगुलेशन इसके उपावृद्ध अनुसूची में वर्णित, में कतिपय संशोधन करने की प्रस्तावना करती है तथा जिन्हें दिल्ली विकास (वृहत्त योजना और क्षेत्रीय विकास योजना) नियमावली, 1965 के अधीन निर्धारित पद्धति के अनुसार, दिनांक 4 अक्टूबर, 1975 की सूचना संख्या एफ-20 (4)/75-एम० पी० में प्रकाशित किया गया था तथा सूचना की तारीख से तीन दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे जैसे कि उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) में प्रपेक्षित है;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र के उक्त जोनिंग रेगुलेशन और भूमि प्रयोग के सम्बन्ध में आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली की वृहत्त योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, दिल्ली की वृहत्त योजना में, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन:

जोनिंग तथा उप-विभाजन से संबंधित खण्ड (क) (जोनिंग रेगुलेशन वृहत्त योजना के मूलपाठ का अध्याय-2) में "प्रयोग जॉनों आवश्यकताओं के बारे में व्यवस्था" शीर्षक के पैराग्राफ (5) में पृष्ठ 55 पर ऊपर की पंक्ति संख्या 3 में बाहिनी और लिखित "से कम नहीं" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द लिखे जाएंगे:

"दो रिहायशी एककों के लिए प्रत्येक मंजिल पर एक इकट्ठे रिहायशी एकक वगैर बरसाती मंजिल के दो मंजिले भवन के लिये लगभग 3.3 वर्गमीटर (40 वर्ग गज)"।

[सं० जे० 13037/(122)/75-यु०डी०आई०]
के विश्वास, उप सचिव

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 27th January, 1976

S.O. 1339.—Whereas Certain modifications which the Central Government proposed to make to the zoning regulations applicable to residential plots in the Master Plan for Delhi under Section 11-A of the Delhi Development Act, mentioned in the Schedule hereto annexed, and published in the manner as prescribed under rule 6 of the Delhi Development (Master Plan & Zonal Development Plan) Rules, 1959 vide notice No. F-20(4)/75-M.P. dated the 4th October, 1975, for inviting objections and suggestions within a period of 30 days from the date of notice as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act.

And whereas, the Central Government after considering the objections and suggestions with regard to the said zoning regulations and the land use of the area mentioned in the Schedule have decided to modify the Master Plan for Delhi. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications to the Master Plan for Delhi with effect from the date of publica-

tion of this notification in the Gazette of India, namely :—
Modifications :

In paragraph (5), entitled 'Provision regarding requirements in use zones', occurring in Section (A), (Zoning Regulations—Chapter II of the Text of the Master Plan), dealing with zoning and sub-division regulations, for the words "but not less" occurring on page 55, right-hand side, line 3 top, the following words shall be substituted, namely :—

"for two dwelling units, one on each floor. And about 33 sq. metres (40 sq. yards) for single dwelling unit—two storey building without a barsati floor".

[No. J-13037/122/75-UDI]

K. BISWAS, Dy. Secy.

पुर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1976

का०प्रा० 1340.—लोक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारी की बेवखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सहायक निदेशक (पुनर्वास), शरणार्थी पुनर्वास निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार को जो कि सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है तथा यह भी निदेश देती है कि उक्त अधिकारी द्वारा भारत सरकार, पुनर्वास विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन तथा पश्चिम बंगाल राज्य में बेहला तथा बान हुगली कालोनियों में स्थित सार्वजनिक स्थानों के संबंध में उक्त अधिनियम के द्वारा या इसके अन्तर्गत सम्पदा अधिकारियों को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग तथा उन्हें सौंपे गए कार्यों को किया जाएगा।

[संख्या 32(6)/75-प्रार०ई०]

शान्ति लाल, उप सचिव

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 22nd March, 1976

S.O. 1340.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Assistant Director (Rehabilitation), Refugee Rehabilitation Directorate, Government of West Bengal, being gazetted officer of Government, to be estate officer for the purposes of the said Act, and further directs that the said officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act, in respect of public premises in Behala and Bon-Hooghly colonies in the State of West Bengal and under the administrative control of the Government of India in the Department of Rehabilitation.

[No 32(6)/75-RE]

SHANTI LAL, Dy. Secy.

भ्रम मंत्रालय

प्रारोह

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1976

का० प्रा० 1341.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि हमसे उपाबद्ध प्रमुखों में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स राबिनसन, मुम्बई के प्रबंध

तल से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, मुम्बई को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स राबिनसन, कनारा बैंक बिल्डिंग, 15/17, मंगलोर स्ट्रीट, बैलार्ड एस्टेट, मुम्बई-400001 के प्रबन्धतंत्र की 6 अगस्त, 1975 से श्री विश्वनाथ आधव, स्थायी खपरासी की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[स० एल. 31012/1/76-डी-4(ए)]

नन्द लाल, अनुभाग अधिकारी (i) विशेष

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 19th February, 1976

S.O. 1341.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Robinsons, Bombay and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Robinsons, Canara Bank Building, 15/17, Mangalore Street, Bailard Estate, Bombay-400001, in terminating the services of Shri Vishwanath Adhav, permanent peon, with effect from 6th August, 1975 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-31012/1/76-D. IV(A)]

NAND LAL, Section Officer, (Spl.).

New Delhi, the 24th March, 1976

S.O. 1342.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bankola Colliery of Coal Mines Authority Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th March, 1976.

**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
AT CACUTTA**

PRESENT :

JUSTICE E. K. MOIDU . . . PRESIDING OFFICER

Reference No. 23 of 1975

Parties :

Employers in relation to the management of Bankola Colliery of Coal Mines Authority Limited.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Sri N. Das, Advocate, with Sri B. N. Lala, Asstt. Chief Personnel Officer, Sri P. N. Singh, Area Industrial Relation Officer, Area VI. Sri P. S. Lall Singha, Sr. Personnel Officer.

On behalf of Workmen—Shri B. S. Azad, General Secretary, Khan Shramik Congress.

State : West Bengal

Industry : Coal Mines

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by their Order No. L-19012/6/74-LRII/DIII A, dated 21-3-1975, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Bankola Colliery of Coal Mines Authority Limited and their workmen for adjudication to the Tribunal. The reference reads :

"1. Whether the refusal of Shri Radhe Turi, Dresser of Bankola Colliery of Coal Mines Authority Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan, on 21-3-1974 to cut coal in addition to his job of a Dresser was justified ?

II. Whether the suspension of Shri Turi, Dresser for three days with effect from 6-5-1974 to 8-5-1974 by the Management of Bankola Colliery is justified ?

III. If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The workman Shri Radhe Turi alleged that he had been wrongfully suspended from service on 6-5-1974 to 8-5-1974 on the allegation that he failed to execute the order of the Mining Sirdar on 21-3-1974 when he directed him to dress the floor of the mine. According to the workman, as a Dresser he was not bound to cut any coal either on the floor or in any other part of the mine but his work was only to dress the coal. It is alleged that on 21-3-1974 he was directed to cut coal and he refused to cut it. He also disputes the propriety of the suspension order and alleges that the order of suspension shall be set aside with full wages and other benefits which had accrued to him.

3. The management on the other hand contended in their written statement that the workman refused to dress the floor when he was directed to do so by the Mining Sirdar on 21-3-1974 and the refusal of the workman to dress the floor is an act of disobedience to the lawful order which he was directed to execute and as such he had been rightly punished. It is further stated that a domestic enquiry had been conducted against him and that the punishment in question was given, taking into consideration all the circumstances. It is also alleged that in view of the earlier settlement between the Union of the workmen and the management all the outstanding disputes with the workman had finally been settled before the Assistant Labour Commissioner and that the reference therefore is not sustainable.

4. The management did not rely upon the domestic enquiry. It is in evidence that the management issued a chargesheet marked Ext. M-5 to the workman and that the workman had filed his explanation to the chargesheet. The explanation is marked as Ext. M5(a). The charge is now sought to be has been examined as witness No. 1 for the management. He proved through an officer of the Coal Mines Authority. He proved the charge against the workman that on 21-3-1974

while the workman was on duty as Dresser in the South-east area of No. 1 Pit of the coal mines, he was found to be sitting idle though the Mining Sirdar had asked him to dress the floor coal and that he disobeyed his order refusing to dress the floor coal. That evidence has not been rebutted. The evidence of the officer is conclusive and it could be relied upon. The charge is, therefore, proved against the workman. The workman is, however, not bound to cut any coal from the floor of the mine. But it is established that he had refused to dress the floor.

5. The charge having been proved against the workman the only question is as to the punishment to be imposed upon him. In this regard reference has to be made to a settlement, the original of which is marked as Ext. M-4, dated 10-1-1975. That settlement was brought out in the presence of the Assistant Labour Commissioner between the workman represented by the Union as well as the management. It is in evidence that consequent upon his suspension the workman had also been dismissed for a subsequent disobedience of a similar order. The settlement, Ext. M-4 related to that dismissal order. In the body of Ext. M-4 reference is however made as regards the suspension order in question. But in the terms of the settlement the suspension order was not taken into account and the order of dismissal was only made the subject matter of the settlement. The operative portion of the settlement pertaining to the dismissal is that the period of his unemployment from 19-6-1974 as a result of the dismissal order shall be treated as leave without pay for the purpose of continuity of service only and the workman shall have no claim for any wages for the said period. It has to be admitted that the suspension order was not referred to at all in the operative portion of the settlement. Therefore, in view of the lineancy shown to the workman in the terms of the settlement regarding the period of dismissal, I feel that the same type of punishment can be imposed on the workman for the period of his suspension. So, the workman shall be treated as on leave without pay for the period from 6-5-1974 to 8-5-1974 getting continuity of service as well as other benefits if any to which he would be entitled except the salary for those three days of suspension.

6. In the result, an award is passed answering the first part of the reference against the workman to the effect that he was not directed to cut coal in addition to his job of Dresser on 21-3-1974 and that the second part of the reference is answered in favour of the workman to the extent that the period of his suspension from 6-5-1974 to 8-5-1974 shall be treated as on leave without pay subject to his right to get continuity of service as well as other benefits to which he would be entitled. No other direction is necessary in the matter.

Sd/-

E. K. MOIDU, Presiding Officer.

[No. L-19012/6/74/LRII/D-III B]

S. H. S. IYER, Section Officer, (Spl.)

Dated, Dibrugar Camp.

The 10th March, 1976.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1975

का० प्रा० 1343.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 52) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व सामाजिक सुरक्षा विभाग की अधिसूचना सं० का० प्रा० 3291, तारीख 15-10-1965 को, जहाँ तक उसका सम्बन्ध श्री अरविन्द खान से है, विच्छिन्न करती है।

[सं० ए० 12016(12)/75-वी एफ I]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

New Delhi, the 26th March, 1976

S.O. 1343.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Department of Social Security No. S.O. 3291 dated the 15th October 1965 in so far as it relates to Shri Arbinda Khan.

[No. A-12016(12)/75-PF. I]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 24th March, 1976

S.O. 1344.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Cum Labour Court No. 3 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the 20/21 Pits Murulidih Colliery of M/s. Bengal Coal Co. Ltd., P.O. Mohuda, Distt. Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 11th March, 1976.

**CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-
LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD**

Reference No. 98 of 1969

Presiding Officer—Shri S. N. Johri, B.Sc. LL.M.

PARTIES

Employers in relation to the management of No. 20/21 Pits Murulidih Colliery of M/s. Bengal Coal Co. Ltd., P.O. Mohuda, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen represented by Hindustan Khan Mazdoor Sangh.

APPEARANCES:

For Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate represented the Bharat Coking Coal Ltd.

For Workmen—Shri Gurbachan Singh, Advocate.

Industry: Coal.

State: Bihar.

Dhanbad, the 28th February, 1976

AWARD

A reference under Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 has been made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. 2/166/69-LRII dated 15-12-1969 projecting the following question for adjudication by this Tribunal:

“Whether the management of 20/21 Pits Murulidih Colliery of M/s. Bengal Coal Co. Limited, P.O. Mohuda, Dist. Dhanbad, was justified in dismissing Shri Ruplal Mahato, Foreman Incharge (Electrical) with effect from the 20th March, 1969? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. It is not disputed by the old management i.e. M/s. Bengal Coal Company Limited, that Shri Ruplal Mahato was Foreman Incharge (Electrical) at Pit Nos. 20/21 of Murulidih Colliery and was drawing a salary of about Rs. 500. On 12-2-1969 a chargesheet was framed and served upon him that he remained absent without leave or permission and without justifiable cause from 19-1-1969 to 11-2-1969. After Shri Mahato's reply to the charge on 13-2-69, enquiry was started on 21-2-1969 after due notice and in presence of Shri Mahato himself, by Sri S. C. Mallick, Personal Officer of the colliery. After the examination of the first witness an incident flared up between the said enquiry officer and Sri Mahato on the question of faithfully recording the testimony of the second witness. Thereafter no

witness was examined in presence of Sri Mahato. Enquiry Officer submitted his enquiry report on 5-3-1969 and the management accepting that report dismissed Sri Mahato on 20-3-1969.

3. There is a background of this charge. Sri Mahato remained absent on 8th & 9th September, 1968 and again from 13-9-1968 on wards. Wages for the month of September, 1968 had already been paid to him. He was served with two chargesheets No. 5468 dated 13-9-1968 for the absence of 8th and 9th September, 1968 and No. SCM/OF-2 dated 3-10-1968 for the absence from 12-9-68 to 30-9-68. Reply to the said chargesheets was filed. Enquiry was held and vide Order No. SCM/OF-2 dated 15-1-69 a punishment of 10 days' suspension was awarded by the management. Later on it was specified that the period of suspension commenced on 7th and ended on 16th October, 1968. Registered letter communicating that information was served upon Sri Mahato on 10-2-69 along with notice dated 6-2-69 that he is being marked absent from 19-1-69. This absence from 19-1-69 to 11-2-69 formed the subject matter of the present charge culminating in his dismissal. Admittedly no formal order of suspension (except the one for ten days by way of punishment) was never passed against Sri Mahato but he was not allowed to join duties and no wages were paid to him from 1-10-68 onwards.

4. General Secretary of the Hindustan Khan Mazdoor Sangh raised this industrial dispute. The case of the Sangh is that Sri Mahato was victimised because he was the Secretary of the local branch of the union. The enquiry was entrusted to Sri Mallick who had personal bias against Sri Mahato because the latter did not accede to the inducements of the former to work for the rival union which was working under the leadership of one of the relatives of Sri Mallick.

5. Sri Mahato had taken leave for 8th and 9th September and had applied for one month leave from 13-9-68. However he did not avail full period of leave and returned back and resumed the duty on 3-10-68. He was actually paid full wages for the month of September 1968. From 6-10-68 he was again illegally stopped from work and his protest representation remained unheeded. The enquiry on chargesheets dated 13-9-68 and 3-10-68 mentioned above resulted in the finding of guilt against him. Vide order dated 15-1-69 a punishment of 10 days suspension was awarded to him. Alleged service of this order on 18-1-69 through peon book has been denied by the workman. According to him this order was for the first time served upon him on 19-1-69. It did not specify the dates of the commencement and termination of the punishment of suspension. However he submitted the joining report on 20-1-69 and again on 21-1-69. At the same time he sought clarification of the order dated 15-1-69. The clarification was specified that the punishment of suspension shall be deemed to have commenced on 7-10-68 and shall be deemed to have come to an end on 16-10-68. Still those joining reports of 20-1-69 and 21-1-69 were not considered. On the other hand along with the letter dated 23-1-69 the management enclosed another letter dated 6-2-69 which also reached the workman on 10-2-69. In this letter dated 6-2-69 the workman was informed that he was being marked absent from 19-1-69. A protest letter dated 12-2-69 was sent denying the endorsement on the letter dated 23-1-69 that it was sought to be served through peon but as it was not accepted so it was being sent by registered post. This letter of protest was not accepted by the management hence it was sent by registered post. The workman was thus kept idle from 6-10-68 without a formal order of suspension.

6. The enquiry by Sri Mallick was not proper. Enquiry Officer became enraged when Sri Mahato pointed out to him that he was not recording the statement of second witness faithfully. Sri Mahato was turned out. No witness was examined thereafter. The Enquiry Officer fabricated the statements of two more witnesses after the incident. He had no notice and opportunity to cross-examine them. He was not called upon to produce evidence in defence or to explain the circumstances appearing against him. Punishment was too harsh and disproportionate. Sri Mahato was a workman drawing less than Rs. 500/- and the union had raised industrial dispute with the management before taking the matter to Asstt. Labour Commissioner.

7. M/s. Bengal Coal Company Limited raised preliminary objection that there was no industrial dispute firstly because no dispute was ever raised with the management and secondly because Sri Mahato was not a 'workman' as defined in the provisions of Industrial Disputes Act; he was occupying supervisory post and his basic pay was more than Rs. 500/-. It was alleged that there was no case of victimisation. Management treated him under suspension from 1-10-68 onwards though no formal order was passed in writing. The letter specifying the punishment of 10 days suspension was served upon Sri Mahato on 18-1-69 by peon book hence he should have joined at least on 19-1-69. He did not join on that date hence he was chargsheeted for his absence from 19-1-69 to 11-2-69.

8. Enquiry was proper. Allegations of bias against Sri Mallick have been denied and it has been alleged that Sri Mahato himself abused Sri Mallick and left the place of his own accord. Enquiry Officer therefore proceeded further with the enquiry and the punishment was commensurate with the delinquency. After the evidence was recorded in part in this reference the company sent a letter to this Tribunal that due to nationalisation of the colliery, it was not interested in the case and thereafter did not put in appearance on the further dates of hearing.

9. The case of B.C.C. Limited is that even if the enquiry was held to be defective, B.C.C. Limited was not bound to reinstate Sri Mahato or to pay the wages for the idle period. It pleads complete protection and immunity from liability by virtue of Sections 9 and 28 of Nationalisation Act.

10. Sri Mahato WW-8 has, in support of the pleadings in the rejoinder, stated on oath that he sent the letter dated 2-4-69 (copy Ext. W-25 to the management raising the dispute before the employer prior to the formal raising of the dispute before Asstt. Labour Commissioner. Ext. W-26 is the certificate of posting of that letter. There is no specific denial or rebuttal of this evidence. Thus it is clearly established that dispute had been raised before the employer and when no relief was granted by the employer the union took the matter to Asstt. Labour Commissioner. There also the management participated in conciliation proceedings and did not raise the objection that dispute had not been raised before it. The first preliminary objection has thus no force.

11. The other allegation is that Sri Mahato was not a workman because he was performing supervisory duties and was drawing a salary of more than Rs. 500/- per month. Sri Mahato has stated on oath that his salary was Rs. 425/- per month only. There is no rebuttal to this evidence. The wage sheet Ext. M-7 clearly appears to be tempered document. Sri Mahato while admitting his signature on it clearly stated that there were no overwritings when he signed the wage sheet. Rs. 637.50 were paid for 65 days which means the rate was something less than Rs. 300/- per month. At another place Rs. 445/- were paid for 39 days at the specified rate of Rs. 425/- per month. This calculation does not appear to be correct. In any case these overwritten figures indicate that Sri Mahato was drawing a basic salary of less than Rs. 500. No witness was examined by the management on this point. It is therefore held that Sri Mahato was drawing a salary of less than Rs. 500/- per month. Looking to the provisions of Section 2(s) of Industrial Disputes Act the nature of duties performed by a person getting less than Rs. 500/- per month salary are irrelevant and he will be deemed to be a workman. This finding puts an end to the second preliminary objection.

12. On merits it is an obvious case of victimisation. Management was after Sri Mahato since October 1968 and somehow wanted to subdue him failing which it wanted to terminate his services. Admittedly he was not allowed to join duties from 1st or 3rd or atleast 6th of October 1968 whatever may be the case. The date is not very material. There was no order of suspension and no suspension allowance was paid. The case of the management is of presumed suspension. However such a presumed suspension, if at all, could only be for the period of the pendency of enquiry. Final orders in that enquiry were passed on 15-1-69 and that order was communicated to Sri Mahato on 19-1-69. After that date there was no occasion for the presumed

suspension to continue. On 20-1-69 Sri Mahato submitted joining report seeking permission to resume his duty. That letter is Ext. W-28. No orders were passed on it, nor he was allowed to join duty. Again on the next day i.e. on 21-1-69 he submitted another letter Ext. W-29 seeking permission to resume duty. The management sat silent over it as well. Suspension during the pendency of enquiry, even according to management, terminated on 16-10-68 and that presumed suspension should then have come to an end. The management should have allowed Sri Mahato to join duties at least on 20th or 21st January when he reported for resumption of duty vide aforesaid applications. There was no point in postponing the decision on those two applications.

13. Moreover when the punishment of suspension was only for 10 days and that period ended on 16-10-68, how could interim suspension continued after that for an indefinite period and that too presumably? There is no sanction of law for such a procedure and it was nothing but an act of victimisation. It is strange that without passing any order in writing and without communicating the fact to the employee the management simply did not allow him to work and now when the validity of such a procedure has come to be challenged before this Tribunal the management has come forward with a plea of presumed suspension. All this is nothing but highhandedness indicative of malus to victimise for some ulterior reason.

14. The management passed a vague order of punishment of 10 days suspension in the previous enquiry without specifying the dates. The vagueness was purposeful and was accordingly utilised for the ultimate charge. The employee requested the management vide letter Ex. W-27 dated 20-1-69 to specify the dates so that he could join back on the expiry of the period of punishment. Reply to it dated 23-1-69 was served upon him as late as on 10-2-69, it is Ext. W-15. This reply contains an endorsement that Sri Ruplal Mahato refused to take delivery of it through peon book. Hence it was being sent by registered post. That endorsement is not signed by anybody. It does not specify the date on which the letter was sent through peon book. Name of the peon is also not given in the endorsement. However the management did examine the Peon Sri Sanichar Ram MW-1 to prove such refusal by Sri Ruplal Mahato, but that witness has denied on oath that he came across Sri Mahato or that Sri Mahato had refused to accept the letter. He has stated that Sri Mahato was not in his house hence he could not be served. To the same effect is the statement of Sri Mahato. The endorsement is thus proved to be false.

15. Moreover it does not sound to reason as to how a workman who had himself demanded specification of dates, should refuse to accept the letter specifying the same? How Sri Ruplal Mahato stood to gain by such refusal? Thus circumstantially also this endorsement appears to be false. It is not clear why it was necessary to send this reply by registered post if it was believed that the workman had really refused to accept the same through peon book. That peon book has not been produced and what endorsement was infact was made by Sri Sanichar Ram on the peon book has been kept back. Presumably that endorsement did not support the management's case and whatever Sanichar Ram is saying appears to be having the nucleus of truth. In any case in the normal course the letter should have been sent by registered post on or about the date on which the workman had so refused to accept it through peon book. Why the management suddenly woke up from the long spell of slumber after about two weeks to send the same by registered post? It must have thought that it will not be possible for it to prove the said refusal successfully. Hence in order to fortify the stand this step was taken. This again supports the fact that Ext. W-15 contains a false endorsement that the letter was sought to be delivered through peon book and was refused by Sri Mahato.

16. In my opinion all this procedure was adopted with the object that the letter specifying dates may not reach Sri Mahato before 6-2-69 when the other letter was issued informing him of absence from 19-1-69. This was only a device to prepare a ground for a fresh charge. With the receipt of previous letters management was sure that as soon as Sri Mahato will receive such a clarification he would rush forward to resume his duty. In any case Sri

Mahato had already forestalled management's trick by submitting reports on 20th and 21st January, 1969 seeking permission to resume duty. Making such a false endorsement indicates want of integrity on the part of the management and reflects its spirit to victimize the workman. All these dishonest tactics confirm that the management was out to somehow expel Sri Mahato from the service.

17. All this discussion further proves that the charge of absence from 19-1-69 was basically false and malicious. In fact Sri Mahato was kept out of employment, was not allowed to resume duties in spite of his prayer to do so and yet was charged for wilful absence from 19-1-69. This by itself is sufficient to vitiate the enquiry.

18. There are two versions of the incident which took place on 21-2-69. According to Sri Mallick Sri Mahato did not want him to record something which the witness had said. Sri Mallick did not allow that indulgence hence Sri Mahato became enraged and he left the place. Thereafter Sri Mallick recorded the statements of two more witnesses. According to Sri Mahato Sri Mallick was not faithfully recording the statements hence he raised the objection. This enraged Sri Mallick who abused him and turned out of the office. Obviously out of the two versions, the version of Sri Mahato appears to be correct when looked in the background of the circumstances discussed above. Ratan Bahadur WW-2 was a Peon present just outside the room where this incident took place. He heard Sri Mallick shouting and talking loudly. This means that not Sri Mahato but Sri Mallick was in fact enraged. He has further stated that Sri Mallick called him inside and asked him to remove Sri Ruplal Mahato forcibly out of the office. Accordingly he asked Sri Mahato to go away. Thus Sri Ratan Bahadur has supported the version of Sri Mahato. He is very clear on the point that Sri Ruplal Mahato did not raise the voice.

19. Sri Mallick stated that after Sri Ruplal Mahato had left he recorded the statements of Sri S. P. Chatterjee and Sri Sanichar Ram. Even this statement has been proved to be false by overwhelming evidence. Sri Ratan Bahadur WW-2 again stated that after about 15 minutes of the incident Sri Mallick also left and in the meantime no other person was seen with him in the office. This means that no statement of any witness was recorded that day. Sri Sanichar Ram WW-1 has been examined. He clearly stated that he did not make any statement before Sri Mallick. He was asked to sign a paper and he did so. Sri S. P. Chatterjee WW-3 has also stated that he did not make any such statement during the course of enquiry before Sri Mallick. He was asked to sign. At first he refused to do so but thereafter he was prevailed upon to sign the statement. It is thus clear that the enquiry itself was bogus, the statements of these two very material witnesses were not taken down before Sri Mahato. They were made to sign fabricated statements which they were not willing to give. If the statements of these two persons are excluded and the statement of witness No. 2 is also excluded because full opportunity of cross-examination was not given, there remains no evidence whatsoever to warrant any punishment.

20. Thus looked at from any angle there appears to be a case of no evidence in respect of the charge and the enquiry was obviously a bogus one. The dismissal order of Mahato is quashed as invalid. He will be entitled to all the wages from the past employer upto the date of nationalisation of the colliery as if he was never dismissed.

21. This brings us to the question of liability of Bharat Coking Coal Limited to reinstate and to pay the wages of Sri Mahato from the date of nationalisation.

22. Bharat Coking Coal Limited is successor in interest of M/s. Bengal Coal Co. Limited. Sections 4 & 5 of Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 provide for the transfer and vesting of 'the right' title and interest of the owners' in the Central Government. Section 7 empowers the Government to direct vesting rights in a Govt. Company. Section 5, 8 & 9 do envisage safeguards against previous encumbrances and liabilities including those liabilities which arose out of the acts of the old employers. But Section 17 envisages continuity of the service of the employees and thus the continuity of the business in its entirety. Chapter III provides for the way in which the compensation amount

is to be disbursed to the old companies after the discharge of liabilities as far as possible. Chapter IV imposes a liability on erstwhile managers to deliver all assets to the new company and its managers. Thus what is envisaged is complete transfer of all assets and business of which continuity is maintained in all respects except the change of ownership. As said above Section 17 guarantees continuity of service of employee on the same terms so that under the proviso to Section 25FF of Industrial Disputes Act they do not get a right to claim compensation for termination of service from the old employer.

23. In Ankpaila Cooperative Agricultural and Industrial Society and the workmen A.I.R. 1963 S.C. 1489 broad considerations for deciding whether a transferee concern is successor in interest of the old company or not, were laid down. For similar considerations the Industrial Tribunal came to the conclusion that the transferee society was the successor in interest of the old company and the conclusion was upheld by the Supreme Court. In that case also the same business was continued at the same place by the transferee company without break and almost all the assets were transferred. The transfer was not effected because it was not a going concern as in the case of Hima Bhai Mills Co. Ltd. 1956—II L.L.J. 244. As such that latter case is distinguishable. In the case of New Gujarat Cotton Mills Co. Ltd. 1957—II L.L.J. 194 also the transferee company was held to be successor in interest because all the assets were transferred. There was continuity of business in the same place and under the same name. Even good will had been purchased.

24. Nationalisation, according to the policy of the state as declared under Section 2 of Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 is for so distributing the ownership and contract of the material resources of the community as best to subserve the common good. The words 'common good' as used in Clause (b) of Article 39 of the Constitution of India are wide enough to include the interest of the workman as well. Hence Nationalisation of ownership should subserve the interest of victimised workmen as well. Moreover interpretation of Industrial Laws, and in a way this Nationalisation Act can also be classified as an industrial law, should recognise the socially vital factor of industrial jurisprudence and constitutional mandate of Article 43 which directs the state to secure all workers just and human conditions of work. 'Security of employment is the first requisite of a worker's life' as observed by the Supreme Court in *L. Michael & another Vs. M/s. Johnson Pumps India Ltd.* 1975—I L.L.J. 263. The interpretation should be such as to reconcile the declared directive principle of state policy vide Section 2 (referring to Article 39 of the Constitution) with the undeclared but all pervading directive principles of state policy as envisaged in Articles 41, 42 & 43 of the Constitution so far as industrial laws are concerned. No provision of Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 not even Section 9 of the same can be interpreted as to put the security of service of a victimised labourer to jeopardy, specially when Section 18 of the Act has been incorporated simply with the object of confirming such security.

25. Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 is more concerned with the ownership and managerial aspect and its provisions are meant to save the Government Company from the past liabilities of the owner more so in respect of financial matters such as loans, contract liabilities, payments of wages, back wages, gratuity, bonus, provident fund amounts and other dues of the workers including retrenchment compensation etc. The Act appears to be leaving the labour aspect i.e. the service matters of the workers to the care of the normal law. It is not designed to affect them adversely. Hence to seek an interpretation of Section 9 of the Act in such a manner as to leave worker whose dismissal has been held to be unjustified, to the care of unemployment and starvation would not only be the travesty of argument but will also put at naught the social conscience which should inform the interpretation of Industrial Laws.

26. The absence of non-obstante clause from Section 9 makes it clear that it does not override the provisions of Section 17 of the Act which provides security of continued employment to the workman of the past owner. In a way this is also a liability arising out of the act of recruitment of the workmen made by the past owner and under the normal law as laid down in Section 25FF of the Industrial

Disputes Act the transferee concern was not bound to accept the liability to provide work to all the workmen employed by the past owners. It is with a view to safeguard the workmen against such liability that Section 17 was specifically incorporated in Act No. 36 of 1972.

27. It is true Section 28 of the Act No. 36 of 1972 gives its provisions an overriding effect over such other acts, instruments decrees or orders of Courts or Tribunals as are inconsistent with the provisions of this Act but for providing the relief of reinstatement we have not to seek the aid of any other enactment which may be inconsistent with the provisions of the Act of 1972. In that respect provisions of Industrial Disputes Act are not inconsistent with the provisions of Act No. 36 of 1972. Section 28 of the Act No. 36 of 1972 has thus no relevancy to the present situation.

28. Again it has been argued with reference to clause (b) of Sub-section (2) of Section 9 of the Act of 1972 that no award given after 1-5-1972 in relation to any matter claim or dispute which arose before that day shall be enforceable against the Central Government or Government Company. This widely worded clause according to the learned Counsel for Bharat Coking Coal Limited puts a blanket protection against any such award including an award of reinstatement. Clauses of sub-section (2) are only declarations of the intention of the legislature with respect to the doubts in the interpretation of Sub-Section (1) of Section 9 of the Act. All the inherent limitations, arising out of the policy objectives and purpose of the Act, which inform the interpretation of Sub-section (1) of Section 9 of the Act, as discussed in previous paragraphs, shall normally filter down in these declaratory explanations of its meaning. To be more specific clause (b) of Sub-section (2) of Section 9 makes all such awards relating to past dispute inoperative against Bharat Coking Coal Limited which relate to financial liabilities discussed above as distinguished from the liability of continuance of service. Any other interpretation would give rise to a conflict between the provisions of Section 9 and Section 17.

29. Section 17 opens with the clause 'every person who is a workman within the meaning of Industrial Disputes Act.' Neither the Act of 1972, nor Mines Act nor Coal Mines (Conservation Safety and Development) Act, 1952 (vide Explanation (r) to Section 3 of Act No. 36 of 1972) define a 'workman' and the aforesaid opening clause of Section 17 of Act No. 36 of 1972 specifically imports the definition of 'workman' as given in Section 2(s) of Industrial Disputes Act. According to that definition the expression workman includes 'any such person who has been dismissed, discharged or retrenched' either as a consequence of Industrial Dispute or vice-versa. Thus Section 17 will mean to say that if a wrongfully dismissed or retrenched person is in the fictional or notional employment of the Coking Coal Mine, he shall become a fictional employee of Bharat Coking Coal Limited and will be entitled to be reinstated by Bharat Coking Coal Limited after the adjudication of the dispute in favour of such reinstatement of the workman.

30. There are host of rulings of the Supreme Court and other High Courts which say that a wrongfully dismissed or retrenched workman will be deemed to be continuing in employment as if he was never dismissed or retrenched. It is only on this basis that back wages are granted at the time of reinstatement. Whenever the statutory law or precedent purports to deem a situation it introduces an unreal situation a legal fiction as distinguished from the apparent reality. Full effect must be given to such a statutory fiction. It was so observed by the Supreme Court in State of Bombay Vs. Panduraj Vinayak AIR—1953 S.C. 2014 (246). This deeming thus asks the adjudicator to believe that even though such a worker was out of employment after his unjustified dismissal or retrenchment, he was notionally still under continued employment hence Section 17 would govern the continuance of notional employment of such workman and reinstatement would follow as if a workman under the notional employment of Bharat Coking Coal Limited has been ordered to be reinstated.

31. Such reinstatement is not a consequence of the Act of the past employer as envisaged in Section 9 of the Act but only an incident of the service of the workman and

vindication of his inherent continued right of employment which was now a statutory sanction in the form of Section 17. Past employer had only stood in the way of the exercise of such right of the workman and adjudication has only removed that obstruction. Reinstatement is thus not covered by the mischief of Section 9 of the Act. On principles of Harmonious construction of the provisions of Sections 9 & 17 of the Act only aforesaid interpretation would avoid the conflict. Hence I am of the view that it is obligatory on Bharat Coking Coal Limited to reinstate the said workman.

32. Bharat Coking Coal Limited shall reinstate Sri Ruplal Mahato as follows granting him continuity of service and all benefits of the implementation of Coal Wage Board's recommendations from the date of such implementation. He shall be suitably posted at some place if he reports for duty at the Head Office of Bharat Coking Coal Limited before the Chief Personnel Officer within one month of the publication of this award.

33. The old employer M/s. Bengal Coal Co. Limited shall be liable to pay all back wages from 1-10-1968 till the date of nationalisation and the costs of the union with respect to this reference and Counsel's fee Rs. 50 if certified.

The award is submitted to the Central Government in the Ministry of Labour as required by Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

[No. Z-20012/4/76-DIII A]

New Delhi, the 29th March, 1976

S.O. 1045.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Benedih Colliery, Pure Joyramdih Section of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. P.O. Nawagarh Distt. Dhanbad and their workmen, which received by the Central Government on the 12th March, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 46 of 1975

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

ORDER OF REFERENCE

(Ministry's Order No. L-20012/117/74/LR-II/D-III(A) dt. 5-5-1975).

PARTIES :

Employers in relation to the management of Benedih Colliery, Pure Joyramdih Section of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Nawagarh, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the Employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri Lalit Burman, Secretary,
United Coal Worker's Union, P.O. & Distt. Dhan-
bad.

State : Bihar.

Dated 6th March, 1976.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour sent this reference dated 5-5-1975 to this Tribunal for adjudication of the industrial dispute involved with the following issues framed.

"(1). Whether the action of the management of Benedih Colliery Pure Joyramdih Section of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Nawagarh, Distt. Dhanbad in stopping from work with effect from 9-2-1973, Shri Ozir Mian, Miner, is justified ?

(2) If not, to what relief is the said workman entitled ?".

The case of the workmen is that Sri Ozir Mian, had been working in the Pure Joyramdih Colliery as a Miner from before the take over of the colliery by the Central Government on and from 30-1-1973. Shri Ozir Mian fell sick from 24-12-1972 and took leave formally on account of sickness. After recovery he made an application dated 8-2-1973 for joining duties. The management did not allow him to resume his duties. The management took the plea that the workman's name was not included in the manpower list.

The case of the management is that they have been informed that the name of Ozir Mian was not found in the available statutory records of Pure Joyramdih Colliery on the date of take over i.e. 31-1-1973. Ozir Mian failed to produce any proof of his employment in the colliery prior to 31-1-1973 and the then management did not allow him to join work on 9-2-1973. The action of the management was bonafide and justified.

We are to decide the issue framed in this case on the evidence on record. I must say that the evidence produced by the workmen is too poor. The only evidence forthcoming from the side of the workmen are copies of two letters alleged to have been submitted by the concerned workman before the Overman incharge of that Colliery whose name was Narula. These copies of two letters are alleged by the management to be forged and prepared in one sitting. Let us look to the copies of these two letters namely Ext. W. 1 and W. 2. Ext. W.1 is a copy of letter dated 24-12-72 praying for leave for sickness till recovery and Ext. W.2 is a copy of the alleged letter dt. 8-2-1973 praying for permission to resume duties on recovery from sickness. Ozir Mian examined as WW.1 says that the office copies bear the signature of one Narula, the Overman incharge. WW.1 says that one Baleswar Babu of the Union wrote the body of

the letters. Of course Baleswar Babu has not been examined. Narula has not also been examined by the workman to prove his signature or the circumstances under which he put down his signature. If actually Narula put his signatures on the application, that is not enough. He was certainly not competent to grant leave. There is no endorsement by Narula forwarding the applications to the competent authority who could sanction leave. If for the sake of argument Narula signed the application that does not go to prove the workmen's case that Ozir Mian was a regular workman on rolls. The copies Ext. W.1 and W.2 are unilateral documents which cannot bind the company in the absence of supporting documents or other evidence. It was his case that he was a workman from before the take over. He does not examine any other person who is in the know of things. The workmen do not appear to have called for any document from the other side in support of his case. Admittedly he was not on duty on the date of take over. WW.1 says that he was a member of Coal Mines Provident Fund having worked in the colliery for 7 years. He has not filed a single paper regarding his membership of the C.M.P.F. He did not also call for any papers in this connection. We may now come to the side of Management's evidence. The management has filed an attested copy of B Form Register (Ext. M. 1) in which the name of the concerned workman does not appear. Sri K. B. Dutta was the Manager of the colliery at the relevant time. His evidence is that after take over man power list was prepared. The man power list bear the signature of Sri B. Singh Personnel Officer and Sri N. K. Sinha. It appears that a screening committee was set up after the take over. It also appears that screening committee had Trade Union members. It is true that the signatures of the Trade Union Officials do not appear in the Man Power list. It has not been proved before me that Trade Union Officials must sign the Man Power Lists. So the evidence adduced by the Management does not prove that Ozir Mian was a workman from before the date of take over. I may say in this connection that the reference was made on the demand of the workman that Ozir Mian was a workman. It was more on the workmen to prove that Ozir Mian was a workman who was entitled to be appointed as such after the take over or on the appointed date. The evidence forthcoming from the workmen's side is not satisfactory. May be he was a casual workman, that does not help. The preponderance of evidence is not in favour of showing that Ozir Mian was a workman in the colliery and at the time of take over or on the appointment date. On the evidence on record I cannot persuade myself to accept the workman's case.

In the result, the action of the management of Benedih Colliery, Pure Joyramdih Section of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Nowagarh, Dist. Dhanbad, in stopping from work with effect from 9-2-1973 Shri Ozir Mian Miner is found justified. He is, therefore, entitled to no relief.

This is my award.

K. K. SARKAR, Presiding Officer

[No. L 20012/74/LR II/ IIIA]

R. P. NARULA, Under Secy.

